RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-06, अंक - 33 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 09 मई 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म और प्रयास करें। जबकि सफलता वातावरण और मौके पर निर्भर करती है।

शहीद सरदार भगतसिंह

पहला चुनाव बनाम अंतिम चुनाव, सहानुभूति लहर या महिला सशक्तिकरण...?

माही की गूंज, झाबुआ।

मई की तपती धूप में चुनाव का माहौल भले ही गर्म न हो लेकिन सूर्य भगवान के तेवर तीव्र है। चुनावी सरगर्मी गांव और फलियों में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आम कार्यकर्ता के साथ ही वोटर केवल 13 तारीख का इंतजार कर रहे है ताकि वह वोट करके अपना फर्ज निभा सके। न कोई चुनावी शोर शराबा है न ही वादों और आश्वासनों की लड़ी है। यह चुनाव केवल शीर्ष स्तर के वादों... गारंटीयो और पार्टी के आधार पर ही लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि, इस चुनाव में आम मतदाता के मूड का आकलन करना भी कठिन होता है।

कस्बाई, इलाकों में जरूर बैठकों का दौर चल रहा है नेताओं के भाषण हो रहे हैं ।इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना जरूर प्रशासनिक मशीनरी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला इसके लिए जूटा है कि, कैसे भी करके वोटर घर से निकलकर अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

भूरिया बनाम चौहान

रतलाम संसदीय क्षेत्र पूर्व में झाबुआ-रतलाम संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस सीट पर अधिकतर समय भूरिया सरनेम के व्यक्ति का ही दबदबा रहा और इस चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे कांतिलाल भूरिया ही है यानी वे विजई रहते हैं तो यह परंपरा आगे बढ़ेगी। लेकिन परिणाम विपरीत रहने पर चौहान सरनेम वाली अनीता नागर सिंह सांसद के रूप में दिल्ली में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार है कई बार सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतदाताओं के बीच अपना अंतिम चुनाव बतलाकर सहानुभूति के साथ ही अपने पुराने संबंधों के आधार पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं वहीं उनके प्रतिद्वंदी अनीता चौहान के लिए यह पहला चुनाव है। हालांकि वे दो बार से जिला पंचायत अध्यक्ष है लेकिन उनका चुनावी अनुभव जिला पंचायत सदस्य तक ही सीमित है, बड़े चुनाव में उनके लिए यह पहला प्रयास है। पूरे क्षेत्र के लिए वे नई प्रत्याशी है इसलिए वो केवल और केवल मोदी की गारंटी पर चुनाव में वोट मांगती नजर आ रही है। वो केवल मोदी के कार्यों के भरोसे और मोदी जी को ही पुनः प्रधानमंत्री बनाने का हवाला देते हुए अपने लिए वोट मांग रही है। अब देखना है कि, आम जनता नए प्रत्याशी को मौका देती है या पुराने अनुभवी को प्राथमिकता...? चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी किये जा रहे हैं लेकिन स्थानीय समस्याओं पर दोनों ही दल मोन है। न भाजपा अपने सांसद की उपलब्धियां का जिक्र कर रही है न ही कोई स्थानीय समस्या के निराकरण का कोई आश्वासन केवल मोदी की गारंटी का ही बोलबाला है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत संबंधों और कार्यों का हवाला देते नजर आ रहे हैं।

कैसे बढ़ेगा मतदान प्रतिशत

चुनावो को लेकर प्रशासनिक मशीनरी चुस्त-दुरुस्त है सभी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, दलों का गठन किया जा चुका है, मशीने तैयार कर ली गई है। चुनाव में लगने वाली बसों का अधिग्रहण दिनांक 11 मई से कर लिया जाएगा। मतदान दलों को भेजने के रूट चार्ट बन चुके हैं यानी चुनाव के पूर्व की जाने वाली सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या मतदान प्रतिशत बढ़ेगा...? सरकारी कवायद तो सत प्रतिशत मतदान की है लेकिन आज तक यह आंकड़ा छूना संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रशासन का यह प्रयास है कि, अधिक से अधिक मतदान हो लेकिन कैसे होगा यह यक्ष प्रश्न है तमाम मौसमी स्थितियां प्रतिकूल है। भीषण गर्मी का दौर है, लोग काम की तलाश में पलायन पर है, गांव सुनसान है, ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाना चुनौती है। अभी तक हुए तीन चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत में हुई गिरावट, प्रशासनिक दावों और उसकी हकीकत की कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में रतलाम सीट पर भी मतदान औसत ही रहने की संभावना नजर आ रही है।

कैसे करें मतदान

मतदान करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। एक जागरूक नागरिक की यही पहचान है कि, वो इस लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाए। सभी चुने और सही चुने का मूल मंत्र ही देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के साथ ही उसे मजबूत भी बनाता है। आपको मतदाता पर्ची मिल चुकी होगी, जिसमें आपके मतदान केंद्र की जानकारी अंकित है। यानी आपको किस मतदान केंद्र पर कब और किस समय तक मतदान करना है यह सब जानकारी अंकित है। लेकिन केवल इसके आधार पर आप मतदान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपनी पहचान बताने के लिए अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र भी ले जाना होगा। जिसके आधार पर आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 दस्तावेजों की सूची जारी की है। जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान पहचान परिचय पत्र (वोटर कार्ड) आदि शामिल है, जिसमें से आप कोई भी एक ले जाकर मतदान कर सकते है। आप मतदान केंद्र में सर्वप्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचेंगे वो आपकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद आपको मतदान अधिकारी के पास पहुंचाएगा। मतदान अधिकारी रजिस्टर में आपका सरल क्रमांक और मतदान क्रमांक अंकित कर आपके हस्ताक्षर लेगा तथा आपके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाएगा तथा आपको एक पर्ची जारी करेगा, वह पर्ची लेकर आप मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएंगे, वो आपसे पर्ची लेकर मशीन द्वारा वोट जारी करेगा, उसके बाद आप मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी पसंद के उम्मीदवार के साथ वाला बटन दबाना होगा। बटन दबाने के बाद आप विविपेट मशीन को देखे जिसमें एक लाइट जलेगी और आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसका चुनाव निशान दिखाई देगा। 7 सेकंड तक दिखाई देने वाली यही पर्ची स्वतः मशीन में कट कर गिर जाएगी।

विविपेट मशीन से आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि, आपने वोट जिस प्रत्याशी को दिया उसी प्रत्याशी को आपका वोट गया है। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया प्रत्येक मतदाता के लिए की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को घर से ही वोट देने की सुविधा दी थी और काफी लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने घर से मतदान किया है।

माही की गूंज भी आपसे अनुरोध करता है कि, आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

सभी चुने... सही चुने... पहले मतदान फिर जलपान।

चांद को लेकर एक और खुश खबरी

नई दिल्ली। चंद्रयान-3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता मिले आठ महीने हो चुके हैं। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके दुनियाभर में इतिहास रच दिया था। अब चंद्रयान-2 को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, इसरो के चंद्रयान-2 मिशन ने चांद को समझने के लिए एक और अभूतपूर्व खोज की। चंद्रयान-2 मिशन के हालिया निष्कर्षों से चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटरों के भीतर पर्याप्त जल भंडार की उपस्थिति का पता चला है। इस खोज को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों को चंद्रमा को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) और आईआईटी कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच हुए प्रयास से यह महत्वपूर्ण खोज हुई है।

इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोटोग्रैमेट्री एंड मथैथ सेंसिंग जर्नल में प्रकाशित स्टडी से पता चलता है कि, चंद्र ध्रुवीय क्रेटर में सबसर्फ बर्फ के सरफेस बर्फ की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक मात्रा में होने का अनुमान है। इस खोज के निहितार्थ दूरगामी हैं। इन जल भंडारों तक पहुंच भविष्य के चंद्र मिशनों का समर्थन करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस स्टडी से यह भी पता चलता है कि, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में पानी की बर्फ की मात्रा दोगुनी है। यह अंतर्दृष्टि मिशन योजना और भविष्य के चंद्रमा अभियानों के लिए साइट चयन के लिए काफी अहम है। सबसरफेस वॉटर आइस की उत्पत्ति इम्ब्रियन काल से होती है, जोकि लगभग 3.8 से 3.2 अरब वर्ष पहले था। माना जाता है कि इस जल बर्फ का प्राथमिक स्रोत ज्वालामुखी के इस काल के दौरान निकलने वाली गैस है।

मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं ले रहा चुनाव आयोग, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस

चेन्नई, एजेंसी।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि, वह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दे।

याचिका में कहा गया है कि मोदी के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन उसने सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए मोदी ÷खुद अपराधी÷ हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में कहा गया है, मोदी इन भड़काऊ टिप्पणियों, अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ईसीआई की यह उदारता नागरिकों को गलत संकेत भेजती है और हमारे देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है। इस मामले का उल्लेख आज न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंदीरा और आर कलाईमथी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया।

हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले इस मामले को पहले रजिस्ट्री के पास ले जाकर रजिस्टर कराए। यह याचिका टीएनसीसी ने अपने अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थागई के माध्यम से दायर की है। उन्होंने आज सुबह कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल के बाद से कई चुनावी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की हैं।

अपनी याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को किसी भी तरह से जीतने का प्रयास कर रही है, और इसलिए, सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी अभियान में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद मुसलमानों को ÷घुसपैठिया÷ और ÷अधिक बच्चे पैदा करने वाला÷ कहा था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र के बारे में भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी की है और भाजपा नेता को ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने से रोका जाना चाहिए।

मोदी की उस टिप्पणी पर भी विरोध दर्ज कराया गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ÷विपक्ष की जीत का मतलब होगा कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों के हाथों में चली जाएगी।÷ टीएनसीसी अध्यक्ष ने कहा कि, उन्होंने 1 मई को चेन्नई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मोदी के ÷अपमानजनक बयानों और सांप्रदायिक बयानबाजी÷ के खिलाफ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया गया। हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, टीएनसीसी अध्यक्ष ने अब उच्च न्यायालय का रुख किया है और ईसीआई को मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देने की मांग की है।

कांग्रेस को बे मौत मारना हो तो भाजपा का बटन दबाओ - मुख्यमंत्री यादव

प्रत्याशी को नहीं दिया बोलने का मौका

माही की गूंज थांदला।

संत नगरी में थांदला के गौरवशाली संत 108 पुण्यसागरजी महाराज के दर्शन करने का समय नही निकाल पाने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी अनिता नागरसिंह चौहान के लिए प्रचार करने आये।

पेटलावद के आंबापाड़ा में पंडित कमल किशोर नागर की कथा में शामिल होकर हेलिकॉप्टर से थांदला रोड़ शो में शामिल होने आए मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हेलीपेड से बायपास होते हुए मुख्यमंत्री खजूरी पहुँचे, जहाँ बड़ी देर से खड़ें ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया और थांदला रोड़ शो के लिए आगे आगे चलने लगे। मुख्यमंत्री का रोड़ शो नगर के मुख्य मार्गों पर जन समूह का स्वागत अभिवादन स्वीकारते हुए जवाहर मार्ग होते हुए मठवाला कुआ पहुँची जहाँ अपने अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस ने गरीबों का शोषण ही किया है। भीली भाषा में यादव ने कहा, कांग्रेस लुटेरा ने दुतारा री पार्टी है, ये घमण्डिया लोग किसी का भला नही कर सकते है। इनका घमंड रावण की तरह है जिसकी नाभि में वोट रूपी तीर मारकर कांग्रेस को बेमौत मारना है। नरेंद्र मोदी के नाम पर मुख्यमंत्री ने वोट मांगते हुए कहा कि, दुनिया का नम्बर एक देश बनाने के लिए मोदी दिन-रात काम कर रहे है और देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए मोदी ही जाना जाता है। मोदी ने अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए लगाया जिसका खुद का कोई घर नही, उसने गरीबों के घर बनाये, मुफ्त राशन दिया, गैस कनेक्शन दिया, अब फिर से मोदी सरकार बनेगी तो गरीबों को मुफ्त बिजली भी मिलेगी। मुख्यमंत्री, देश के साथ धर्म की बात करने से भी नही चुके। उन्होंनें कहा आज अयोध्या में रामजी खुश हो रहे है, यही नही रावण वध की जगह राम का वध बोलते बोलते रह गए। थांदला में यादव ने मोदी के नाम पर वोट मांगें वही लोकसभा प्रत्याशी को एक शब्द कहने तक का मौका नही मिला जो जनचर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, अजजा प्रदेशाध्यक्ष कलसिंह भाबर, पूर्व सासंद गुमानसिंह डामोर, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया सहित झाबुआ व थांदला के पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की प्रशासनिक व्यवस्था ने किया व्यापार चौपट

मुख्यमंत्री के नगर में रोड़ शो को लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ अन्य स्थानों से आये पुलिस दल ने सुबह से ही नगर का अतिक्रमण व व्यापारियों की दुकानों का सामना हटवाया। वही पूरे बाजार में पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा, जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा तथा व्यापार चौपट हो गया। नगर में रोड़ शो को लेकर ग्रामीणों व नगर जनों में भारी उत्साह था लेकिन मुख्यमंत्री से नही मिल पाने की टीस व जल्दबाजी ने उत्साह फीका कर दिया।

महाकाल की तस्वीर बदल गई है। ऐसे में कृष्ण की जय बोलते हुए उन्होंनें मथुरा साधने का इशारा कर दिया। इस दौरान श्रीराम के स्मरण सुनाते हुए मुख्यमंत्री की जबान फिसल गई, जानकी माता के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए राम की श्रीमती कह गए।

जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन

बेंगलुरु, एजेंसी।

लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को समन भेजा है। कर्नाटक पुलिस ने भाजपा की राज्य इकाई की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ एक विवादित पोस्ट मामले में समन भेजा है। कर्नाटक भाजपा के विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस की राज्य इकाई ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पीएस के समक्ष सात दिनों के भीतर तलब होने को कहा है।

भाजपा के लिए जीत की राह नहीं है आसान...

कांग्रेस से भाजपा में आए नेता भाजपाई कार्यकर्ताओं को कर सकते है नाराज

नागरसिंह व उनके परिवार पर लग रहे आरोप, अड़ा सकते है जीत पर अड़ंगा

माही की गूंज, झाबुआ।

लोकसभा चुनावों का पारा अब गर्मी के पारे के साथ बढ़ता जा रहा है। 13 मई को मतदान होना है और 4 जून को स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी। हार जीत का फैसला 4 जून को होना है। इस लोकसभा चुनाव में जो खास बात देखने को मिल रही है वह बहुत बड़े उल्ट फैर की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। चुनावी मैदान में एक तरफ सत्तादल है जो पिछले 10 सालों से सत्ता की चासनी चाट रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगभग इतने ही समय से सत्ता में आने को छटपटा रहा है। सत्ता में बैठी भाजपा लगातार विपक्ष को चोंट पहुंचाती हुई कांग्रेसी नेताओं को अपने साथ मिलाते दिख रही है। कांग्रेसी दिग्गज नेताओं का भाजपा में जाना कई तरह के संकेत दे रहा है। रतलाम - झाबुआ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी माहौल दल बदलने का चल पड़ा है। देखने में तो यह एक साधारण प्रक्रिया नजर आती है, लेकिन इसके पीछे कई तरह के स्वांग नजर आ रहे है। पहला तो यह कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेसी दिग्गज भाजपा में शामिल होते जा रहे है, कहीं यह एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है। क्योंकि यह तय है कि जो कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे है वे किसी न किसी पद या किसी और लालसा के चलते दल बदल रहे है। मगर यह सिक्के का एक ही पहलू है जो सबको दिखाई दे रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि, भाजपा को खोखला करने के लिए कांग्रेसियों ने रणनीति बनाकर भाजपा में प्रवेश किया हो और समय के साथ वे एक बार फिर अपना काम निपटाकर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। मगर यह सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जबकि कांग्रेस जीतकर सत्ता में काबिज हो जाए। भाजपा में कांग्रेसी घुसपैठ किस तरह की है और क्यों है यह समय के साथ उजागर हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां यह बता रही है कि, कांग्रेसी घुसपैठ से भाजपाई कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष पैदा ना हो जाए। क्योंकि यह भी तय है कि कांग्रेसी दल बदलुओं को भाजपा को तवज्जो तो देना ही पड़ेगी और कहीं इसी आपा धापी में भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो जाए। अगर इस स्थिति में भाजपाई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है तो रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट पर भाजपा की सांसे फूल जाएंगी। इस तरह इस लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत आसान तो नहीं होने वाली है।

जिस तरह से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेसियों की भाजपा में जाने की होड़ मची है वह शायद कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो ना हो, लेकिन भाजपा के लिए यह चिंता का विषय हो सकती है। क्योंकि भाजपा में दल बदलकर शामिल हुए हजारों कार्यकर्ताओं के मन में क्या है और क्यों है, यह कोई नही जानता। अगर दल बदलु कांग्रेसियों में पद की लालसा है तो यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में कार्यकर्ताओं की भरमार है, तो यहां तो दल बदल कांग्रेसियों को कुछ मिलने वाला है नहीं। यह कारण भी नहीं हो सकता जिससे दल बदला जाए। इसके अलावा इसका सीधा सा एक मतलब यह भी माना जा रहा है कि, जिसके राज भाजपा के पास उसे भाजपा में जाना ही होगा वरना सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर कटना तो सेब को ही है। हालांकि यहां एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि, बड़े नेताओं का दल बदलना समझ में आ सकता है लेकिन छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं की ऐसी क्या मजबूरी है, जो उन्हे दल बदलने पर मजबूर कर रही है। न पद की लालसा न कोई उलटे-सीधे धंधे जो इन्हे दबाव की लिस्ट में लाकर खड़ा कर सके। तो फिर ऐसा क्या है जो इन छोटे-मोटे कांग्रेसी दलबदलुओं को भाजपा में जाने के लिए विवष कर रही है। यह बात और हो सकती है कि, क्षेत्र की बजाय वे राष्ट्रहीत में मोदी जी के साथ खड़े हो, लेकिन यह बात भी हजम होने जैसी दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि जब तक क्षेत्र हित की बात नहीं होगी तब तक देशहित का कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल जो भी हो लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्तओं और नेताओं के दल बदलने से कुछ तो होगा जो इस लोकसभा चुनाव में बड़ा फैर बदल करेगा।

वहीं एक तरफ रतलाम-झाबुआ संसदीय सीट इस बार बड़ी रौचक दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया है जो लंबे समय से अपने कद्दावर होने की ताल ठोक रहे है। तो वहीं भाजपा से अनिता नागरसिंह चौहान है जो लोकसभा सीट के लिए नया चेहरा है। हालांकि उनके साथ इस लोकसभा सीट पर मौजूदा प्रदेश सरकार चुनाव लड़ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि, भूरिया का चुनाव प्रदेश सरकार से हो रहा है। मगर इसके विपरीत कांग्रेस के भूरिया पिता-पुत्र इस लोकसभा में लगातार भाजपा की अनिता चौहान व नागरसिंह चौहान के परिवार पर निजी हमले कर रहे है। लगातार प्रेसकांफ्रेंस के माध्यम से नागरसिंह चौहान परिवार पर आरोप लगाए जा रहे है। कहने को तो चुनाव में इस तरह के निजी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि इश्क और जंग में सबकुछ जायज होता है। उसी तरह इस लोकसभा चुनाव में भी सबकुछ जायज मानकर राजनीति की जा रही है। भूरिया के यह आरोप लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही शुरू हो गए थे। कई तरह के गंभीर आरोप भूरिया ने अनिता चौहान और उनके पति वर्तमान प्रदेश सरकार के वनमंत्री नागरसिंह चौहान पर लगाए। भूरिया के इन आरोपों का कोई पुख्ता जवाब नागरसिंह ने लंबे समय तक नहीं दिया। अब मतदान की तरीखें करीब है और एन वक्त पर नागरसिंह चौहान ने अपनी जुबान खोली है। हालांकि नागरसिंह चौहान पहले भी उन पर लगे आरोपों को यह कहते हुए टालते रहे कि जवाब जनता देगी, लेकिन शायद अब नागरसिंह के सब्र का पैमाना छलकने लगा है।

पिछले दिनों नागरसिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दिया। जिसमें वह खुले तौर तीखे तेवर के साथ यह कहते नजर आ रहे है कि, विक्रांत नहीं जानता कि वह किस खेत की मूली है, वो जितना मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसे भुगतना पड़ेगा, वह भुगतेगा। असल में नागरसिंह चौहान के सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियों में उनकी छवि साउथ इंडियन फिल्मों के विलेन वाली दिखाई पड़ती नजर आ रही है। अंदाज और तेवर कुछ ऐसे जिसमें द्वेषता, गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दे रही है। नागरसिंह पूरी तरह से भूरिया के आरोपों से तिल मिलाए नजर आ रहे है।

यहां एक प्रश्न फिर जन्म लेता दिखाई दे रहा है कि, क्या वाकई भूरिया द्वारा लगाए गए आरोपों में सत्यता है। क्योंकि जब-जब भूरिया ने प्रेसवार्ता की है तब-तब नागरसिंह चौहान पर एक नया आरोप लगाया है। लंबे समय से नागरसिंह चौहान ने इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब जबकि उन्होने जुबान खोली है तो वह सब्र के पैमाने से छलकती नजर आ रही है। भुगतने वाला बयान नागरसिंह की तरफ से खुली धमकी दिखाई दे रहा है। अगर भूरिया के आरोपों में सच्चाई है तो फिर नागरसिंह चौहान की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि किसी बात का खंडन करने की बजाय भुगतने की धमकी, आरोपों का सही जवाब नहीं होता। इसका सीधा अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि, भूरिया के द्वारा लगाए गए आरोप सही है। हालांकि माही की गूंज इन आरोप-प्रत्यारोपों की इस जंग में किसी तरह का कोई दावा या पुष्टी नहीं करता, लेकिन जिस तरह से दोनों ही दलों में बदजुबानिया चल रही है वह किसी न किसी को तो चोंट पहुंचाएगी ही।

भूरिया द्वारा लगाए जा रहे आरोप नागरसिंह चौहान व उनकी धर्मपत्नि अनिता चौहान के लिए चुनौती पैदा करते दिखाई दे रहे है। अगर भूरिया इन आरोपों के साथ नागरसिह की यही छवि मतदाताओं के बीच रखते रहे तो यह तय है कि नागरसिंह चौहान व उनके परिवार पर लग रहे यह आरोप भाजपा व अनिता चौहान की जीत पर अड़ंगा अड़ा सकते है।

वैसे भी नागरसिंह के भुगतने वाले बयान पर पलट वार करते हुए डॉ. विक्रांत भूरिया ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। विक्रांत ने अपनी प्रतिक्रिया में नागरसिंह चौहान को कहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं और सर्जन हूं, हमने अच्छों-अच्छों का इलाज किया है। हम लोगों का इलाज उनकी जान बचाने के लिए करते है। हालांकि विक्रांत भूरिया की इस बात को भी पढ़े लिखे अंदाज में धमकी देना ही कहा जा रहा है।

कुल मिलाकर नागरसिंह चौहान अपने व परिवार पर लगे आरोपों से इस चुनाव में नुकसान उठा सकते है और दूसरी तरफ अगर दल बदलु कांग्रेसियों ने कोई रणनीति अपनाई तो फिर भाजपा और अनिता नागरसिंह चौहान के लिए इस लोकसभा चुनाव में खासी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।

मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान के लिए किया आमंत्रित

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष कुमार टैगोर के निर्देशानुसार व प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के समस्त ग्राम एवं वार्डों में लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें संबंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तारतम्य में नागरिकों को एकत्रित कर 13 मई 2024 को लोकसभा चुनाव में अपने वोट के महत्त्व के बारे में बताया। इस अवसर पर सभी को मतदान की शपथ दिलवाई गयी एवं मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी समझाया गया। साथ ही महिला मतदान प्रतिशत में वृद्धि किये जाने एवं नव महिला मतदाताओं व नव दम्पत्तियों में मतदान के प्रति जानगरूता उत्पन्न करने के लिए महिलाओं एवं परिवारजनों से विशेष आग्रह किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं के घर-घर जाकर पीले चावल देकर मतदान करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी तारतम्य में शुजालपुर शहरी सेक्टर से पर्यवेक्षक सुश्री मंजू दांगी के नेतृत्व में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। पनवाड़ी सेक्टर से पर्यवेक्षक श्रीमती सोमकाला शर्मा के नेतृत्व में, नांदनी सेक्टर से पर्यवेक्षक श्रीमती ज्योति बामनिया, शाजापुर ग्रामीण सेक्टर से श्रीमती प्रीती गुप्ता, मोहना सेक्टर से श्रीमती प्रियंका चंद्रवंशी एवं खोंकराकलां सेक्टर से श्रीमती ममता मनावत के नेतृत्व में मतदाताओं को पीले चावल देकर आमंत्रित किया गया एवं मतदान पर्चियां भी वितरित की गई।

स्वीप गतिविधि का किया आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर के निर्देश पर जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए दाहोद नाके टंट्या मामा की स्मारक पर सकोरे वितरण नगर पालिका परिषद अलीराजपुर द्वारा किए गए। इसी के साथ आजीविका मिशन के कर्मचारियों एवं अधिकारी के द्वारा भी रैली एवं मतदान करने के लिए शपथ ग्रहण कराई गई। जिला अग्रणी प्रबंधक राजेश हसवानी ने बताया कि, जिले की समस्त बैंकों में स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैंक के ग्राहकों को एवं कर्मचारियों द्वारा मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान जिला स्वीप आइकॉन सुधीर जैन समेत संबंधित समस्त बैंक शाखाओं के प्रबंधक आदि भी उपस्थित थे।

प्रज्वल रेवन्ना के पिता को 14 मई तक भेज न्यायिक हिरासत में

बेंगलुरु, एजेंसी।

जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक महिला के अपहरण के आरोप में पूर्व मंत्री रेवन्ना (66) को शनिवार 4 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने उन्हें आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वहीं अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जद (एस) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे रेवन्ना और उनके करीबी सतीश बबन्ना के खिलाफ 29 अप्रैल को एक महिला का अपहरण करने के आरोप में बृहस्पतिवार रात को मामला दर्ज किया गया था। मामला महिला के बेटे की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसने आरोप लगाया था कि, रेवन्ना के बेटे और जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। एसआईटी ने बबन्ना को भी हिरासत में लिया है।

प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के कथित यौन शोषण के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर हाल में सामने आए थे जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच करने के लिए 28 अप्रैल को एसआईटी गठित की थी। इससे पहले, कर्नाटक महिला आयोग ने मामले में जांच को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखा था। हासन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार प्रज्वल (33) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को देश छोड़कर चले गए। वह एसआईटी की ओर से पेश होने का समन दिए जाने के बावजूद उसके सामने हाजिर नहीं हुए।

प्रशासन का स्वीप कार्यक्रम उतर पाएगा खरा या दिखाई दे जाएगा ढकोसला...?

मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ जाए इस पर संदेह...

अंदर खाने सत्तादल को मोटा भाई की चेतावनी

माही की गूंज, झाबुआ।

देश में पहले तीन चरणों का मतदान हो चुका है और इसके आने वाले मतदान प्रतिशत के आंकड़े सभी को चौका रहे है। जिस तरह से इन तीन चरणों में मतदान प्रतिशत घटा है उसने सभी राजनीतिक दलों की नींदें हराम करके रख दी है। सत्ता का 400 पार का नारा अब धरातल से हट चुका है ऐसा माना जाने लगा है। तो सरकार और चुनाव आयोग अब इस कवायद में है कि, आने वाले चरण में मतदान का प्रतिषत बढ़ाया जाए और इसी कवायद को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे है। मगर सत्ताधारी राजनीतिक दल प्रशासन के इस ऐड़ी-चोटी के जोर से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अब अंदर खाने अपने ही लोगों को धौंस-दपट देकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दवाब बनाया जा रहा है। मतदान प्रतिशत घटने पर रवानगी की धमकी भी मंत्रियों तक पहुंच रही है।

इन सबके बीच कठपुतली बना प्रशासन इस मध्यप्रदेश के पच्चिमी छोर पर गुजरात, राजस्थान की सीमा से लगे इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ाएगा यह एक यक्ष प्रश्न है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में शिक्षा, समृद्धि और विकास का अब भी टोटा ही है। यही कारण है कि यहां के मूल निवासी अब भी अन्य प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर है। इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाके इस दौर में भी इतने पिछड़े हुए है कि, यहां अब भी नदी, तालाबों में झीरी खोद कर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। कहने को तो यहां सरकार की कई योजना काम कर रही है, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का लाभ आमजन को लगभग न के बराबर ही मिल पा रहा है। यहां की बजाय अन्य प्रदेशों में इस क्षेत्र के ग्रामीणों व श्रमिकों को अच्छा पैसा और मजदूरी मिलती है। जिसके कारण वे यहां से अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते है। कहा तो यहां तक जाता है कि, झाबुआ-आलीराजपुर का श्रमिक आपको देश के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। आजादी के बाद से दशकों गुजर गए लेकिन इस क्षेत्र के ग्रामीणों और श्रमिकों को अपने निवास स्थान पर अब तक सही मजदूरी, पैसा, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पाया है।

अब जबकि यह साल का वह समय है जब यहां के ग्रामीण पूरी तरह से पलायन कर जाते है। होली के बाद से लेकर मानसून आने तक यहां के ग्रामीण पलायन पर ही रहते है। मानसून की दस्तक उन्हे फिर से यहां खैंच कर लाती है। मगर इस बार साल के इन्ही दिनों में लोकसभा के चुनाव आ खड़े हुए है और वैसे भी यहां के ग्रामीण चुनाव से ज्यादा पलायन और मजदूरी को महत्व देते है तो यहां यह कहना भी गलत तो नहीं होगा कि इस बार चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम ही रह जाए...! हालांकि प्रशासन इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। राजनीकि पार्टियां भी इस पर जोर दे रही है, लेकिन क्या यह मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद सफल हो पाएगी ? इस पर अभी प्रश्न चिन्ह ही दिखाई दे रहा है। हालांकि की प्रशासन की इस कवायद में कई स्वीप कार्यक्रम किए जा रहे है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई माहौल देखने को अब तक नही मिल पाया है। कहने का मतलब यह है कि, क्या मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन सिर्फ ढकोसलेबाजी ही कर रहा है। क्योंकि मतदान को लेकर अब बहुत कम समय बचा है और ग्रामीणों का पलायन पर जाना लगातार जारी है, जिले के ग्रामीण मजदूरों की वापसी अब तक दिखाई तो नहीं दे रही है। पीआरओ से जारी होने वाले स्वीप कार्यक्रम के समाचार रोज सब्ज बाग दिखा रहे है। प्रशासनिक स्वीप कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली भीड़ सिर्फ पीआरओ के समाचारों के साथ तस्वीरों में ही नजर आ रही है। 13 तारीख को मतदान प्रतिशत के आने वाले आंकड़े, तस्वीरों को साफ कर देंगे और प्रशासन इस कवायद में कितना सफल होता है यह भी साफ हो जाएगा। वरना जिले में अधिकारियों के फैर बदल तो वैसे भी होते ही रहते है।

पिछले विधानसभा चुनावों में पलायन पर गए लाखों मजदूरों को बुलाने के लिए प्रशासन ने जो स्वांग रचा था वह सबके सामने है। जिले से लाखों लोग पलायन पर थे और प्रशासन महज कुछ हजार लोगों की लिस्ट व नंबर लेकर फोन पर उन्हे मतदान के लिए बुलाने का ढकोसला कर रहा था। जिले के मजदूरों ने प्रशासन के इस कॉल सेंटर पर जो जवाब प्रशासनिक नुमाईदों को दिए थे वे भी मीडिया के जरिए सार्वजनिक हुए थे। मजदूरों ने खुले तौर पर यह जवाब दिए थे कि, आने-जाने का किराया कौन देगा? बस भेज रहे हो क्या? ऐसे कई सवाल विधानसभा चुनावों के दौरान पलायन पर गए मजदूरों के सुनने को मिले थे। मगर इस बार इस तरह की कोई कवायद प्रशासन की ओर से अब तक देखने व सुनने को नही मिल रही है। हां इतना जरूर है कि, सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला जनपद सदस्य और विधायक के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां या खुद प्रत्याशी इन्हे अपने खर्च पर वाहन भेजकर मतदान के लिए बुलाते रहे है। चूंकि यह लोकसभा का चुनाव है और एक लोकसभा सीट रतलाम-झाबुआ-आलीराजपुर तीन जिलों को मिलाकर बनती है, तो लोकसभा उम्मीदवार पलायन पर गए मजदूरों को पार्टी या अपने खर्च पर बुलाने से तो रहा और प्रशासन के लिए भी यह दूर की कोड़ी ही नजर आता है। मतलब प्रशासन को पलायन पर गए मजदूर मतदाताओं को लाना लोहे के चने चबाने जैसा है। यही कारण भी है जो इस बार के लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने मे मुश्किले पैदा करेगा। प्रशासन की मतदान प्रतिशत बढ़ाने की यह कवायद आसान तो नहीं होने वाली है।

इधर राजनीतिक पार्टियों में भी मतदान प्रतिशत को लेकर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। देश में हो चुके चुनाव में घटे मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक पार्टियों को भी असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि फूटे मुंह हर कोई इस घटे मतदान प्रतिशत को अपने पक्ष में बता रहा है। मगर राजनीतिक हल्कों में इस घटे मतदान प्रतिशत ने नींद उड़ाकर रख दी है। सत्ताधारी दल में इसे लेकर काफी उथल-पुथल दिखाई पड़ रही है। अंदर खाने की खबर रखने वाले बताते है कि, तीन चरणों में मतदान प्रतिशत घटने के बाद पूरा का पूरा सत्ताधारी दल सक्ते में है और केंद्रीय संगठन और पार्टी आलाकमान ने इसको लेकर कई तरह के कदम उठाने भी शुरू कर दिए है। प्रशासन पर सख्ती के साथ-साथ पार्टी में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश सरकारों में मंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर मतदान प्रतिशत घटा तो मंत्रियों पर भी गाज गिरने की बात कही जा रही है। अंदरखाने की खबर रखने वाले बताते है कि मोटा भाई ने मंत्रियों को खुले तौर पर यह धौंस दी है कि, कैसे भी करके अपने क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाओं और अगर जिस मंत्री के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत घटा वह अपनी रवानगी की तैयारी भी कर ले। मतलब साफ है कि प्रशासन, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कुछ करे ना करे, लेकिन सत्ताधारी दल इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चोटी से ऐड़ी तक का जोर लगाने वाला है।

आरोपों के अलावा कुछ नहीं भूरिया पिता-पुत्र के पास

खोई सत्ता पाने को लालायित कांतिलाल

विक्रांत की प्रेसवार्ताएं क्या कांतिलाल को दिला पाएगी जीत...?

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

इस बार लोकसभा चुनावों में अलग ही रंग देखने को मिल रहे है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बहुत पहले से ही राजनीतिक तबकों में ओछापन देखने को मिल गया था, लेकिन जैसे -जैसे चुनाव करीब आते जा रहे है राजनीतिक दलों की बदजुबानियां बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेसी खेमे की अगर बात करें तो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया है लेकिन इनकी जगह इनके बेटे मानों चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हों। कांतिलाल भूरिया ने इस लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान जितनी प्रेसवार्ताएं नहीं की उससे कई अधिक उनके बेटे डॉ. विक्रांत भूरिया ने प्रेसवार्ताएं कर ली। इस लोकसभा में पिता की जीत के लिए विक्रांत ने यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, कांग्रेस और कांतिलाल भूरिया के खेमें में कितनी खलबली मची हुई है। विक्रांत इस रतलाम-झाबुआ सीट पर अपने पिता को जिताने के लिए चोटी से ऐड़ी तक का जोर लगा रहे है। मगर इसमें वे कितने सफल हो पाएंगे यह भविष्य के गर्त में है।

लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से ही विक्रांत भाजपा प्रत्याशी पर लगातार निजी हमले बोल रहे है। जबकि भाजपा प्रत्याशी एक महिला है और वे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेसी खेमे से डॉ. विक्रांत भूरिया लगातार उन्हे निशाना बना रहे है। विक्रांत भूरिया ने महिला नेत्री व उनके परिवार पर जिस तरह के आरोप लगाए है, वे किस हद तक जायज है यह तो वे ही जाने, लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी होने और महिला होने का सम्मान तो अनिता नागरसिंह चौहान को मिलना ही चाहिए। विक्रांत ने इन सारी बातों को नजर अंदाज करते हुए अनिता और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए है।

कांतिलाल भूरिया की नामांकन रैली में जिस तरह से विक्रांत ने अनिता पर तीन बार आत्महत्या करने के प्रयास के आरोप लगाए है, वे एक महिला के सम्मान और उसकी निजता पर कठूरा घात है। जिस तरह से कांग्रेस, महिला सम्मान का रोना हमेशा से ही विपक्ष में रहकर रोती आई है और हालही में अपनी महिला प्रतिद्वदी को सरेआम अपमानित व बेइज्जत कर रही है, उससे कांग्रेस के महिला सम्मान के रोने को घड़ियाली आंसू बहाना ही कहा जाएगा। अब यहां यह समझपाना थोड़ा सा मुश्किल है कि, महिला सम्मान को लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है या विक्रांत और कांतिलाल भूरिया की कथनी और करनी में अंतर है। या फिर कांग्रेस के महिला सम्मान के रोना रोने से भूरिया बाप-बेटा का कोई सरोकार नहीं है। यहां यह कहना भी गलत तो नहीं होगा कि सत्ता हासिल करने के इस खेल में भूरिया बाप -बेटे को सबकुछ जायज ही नजर आ रहा है।

रही बात अनिता चौहान के परिवार पर लगे आरोपों की तो आरोप तो आरोप होता है, किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता यहां यह भी बता देना जरूरी है कि विक्रांत ने यहां अनिता चौहान और उनके परिवार पर आरोप नहीं लगाए है बल्कि उन्हे अपराधी ही घोषित कर दिया है। अनिता के पति नागरसिंह चौहान को विक्रांत ने सीधे तौर पर डाकू, लूटैरा और अपराधी बताया है। रेप की किसी घटना पर अपराधी रिश्ता बताकर चुनावी फायदा उठाने के लिए सीधे तौर पर अनिता नागरसिंह चौहान के परिवार से जोड़कर उन्हे ही अपराधी बताना शुरू कर दिया है।

अब तक विक्रांत ने जितनी भी प्रेसवार्ताएं की है वे सारी की सारी मुद्दों से हटकर निजी आरोपों से भरी पड़ी है। इसी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और भूरिया बाप-बेटे इस बार का लोकसभा चुनाव किस तरह की राजनीति कर जीतना चाहते है। विक्रांत का एक बयान और निजी आरोप के साथ सोशल मीडिया पर सामने आया है कि ''डॉक्टर हूं इलाज करना जानता हूं,''। कहीं न कहीं सीधे तौर पर ना सही लेकिन यह भाषा भी एक धमकी ही है। बस फर्क इतना है कि यह कोई गुंडे की तरह खुले रूप से नहीं दी गई बल्कि यह पढ़े -लिखे डॉक्टर की दबी-छुपी जुबान की धमकी है। हालांकि यह सही है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, मगर कुछ स्थान ऐसे भी होते है जहां क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में खामौशी ज्यादा असर कारक होती है।

एक बात तो तय है कि जीत या हार किसी की भी हो लेकिन इस लोकसभा चुनावों में जिस तरह से एक महिला प्रत्याशी की निजता और परिवार के कर्मों को महिला के माथे मढ़ा जा रहा है, उससे भूरिया बाप-बेटे की महिला सम्मान का तिरस्कार करने वाली छवि ही सामने दिखाई पड़ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट पर राजनीति नहीं बल्कि दो परिवारों की आपसी रंजिश दिखाई पड़ रही है।

समाचार प्रकाशित होने के बाद बौखलाया ठेकेदार, ग्रामीणों ने खोलकर रख दी पोल

माही की गूंज, पेटलावद।

मामलाः ग्राम असलिया में नल जल योजना का

पिछले अंक में माही की गूंज में पेटलावद विकासखंड की ग्राम पंचायत असालिया में नल जल योजना में चल रही अनियमित्ताओं को लेकर ÷असालिया में नल-जल योजना बनी किसानों का सिर दर्द, कार्य भी चढ़ रहा भ्रष्टाचार की भेंट÷ शीर्षक के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसमे बताया था कि, योजना अंतर्गत ठेकेदार के द्वारा जो पाइपलाईन बिछाई जा रही है उसके लिए खोदी गई नाली नियमानुसार न खोदी जाकर कम गहराई की खोदी जा रही है। साथ ही इस दौरान जिस किसी किसान की निजी पाइपलाईन फूटी है उसको ठेकेदार द्वारा सुधार कर नहीं दिया जा रहा है। इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ दे तो कई किसानों की पाइपलाईन खुद किसानों ने अपने खर्चे पर सुधारी है। समाचार प्रकाशित होने के बाद कई किसानों ने गूंज प्रतिनिधि से चर्चा कर अपनी समस्या से अवगत कराया। बताया कि, तड़वी फलिए में करीब 25 निजी पाइपलाईन किसानों की तोड़ दी गई जिसमें से एक या दो को छोड़कर बाकी सब किसानों ने खुद के खर्च पर सुधारी है। ऐसा ही कुछ पंचायत फलिया, भगोरा फलिया में भी है जहाँ किसानों ने ही अपनी पाइपलाईन सुधारी है। वहीं स्कूल फलिए में उपसरपंच बापू , प्रकाश निनामा के साथ कुछ और किसानों की पाइपलाईन ठेकेदार द्वारा सुधार कर दी गई, जो एक मात्र ऐसा फलिया है जहाँ ठेकेदार ने फूटी हुई निजी पाइपलाईन कुछ को छोड़कर बाकी की सुधार कर दी। वहीं कुछ फलियों से ऐसी भी जानकारी मिली कि ठेकेदार के कर्मचारी जिन किसी किसान की पाइपलाईन टूटी थी उनको पाइप का टुकड़ा देकर चले गए लेकिन सुधारने का काम स्वयं किसान को ही करना पड़ा। नाम न छापने के शर्त पर एक युवक ने बताया कि, उसकी पाइपलाईन जिस जगह नल जल वालों ने फोड़ी वहां उन्होंने चार से पांच दिन बीत जाने के बाद भी उसे नही सुधारा। इसके बाद मैंने खुद अपनी पाइपलाईन सुधारी साथ ही मेरी पाइपलाईन के साथ अन्य दो और व्यक्तियों की पाइपलाईन भी थी जिनके निजी संबंध ठेकेदार कर्मचारियों के साथ अच्छे थे फिर भी उनकी पाइपलाईन ठेकेदार कर्मचारियों ने नहीं सुधारी।

भविष्य में ग्राम पंचायत के लिए मुसीबत बनेगी पाइपलाईन

उक्त योजना अंतर्गत डाली जा रही पाइपलाईन अधिकांश जगहों पर जमीन से मात्र एक ही फिट की गहराई में ही डाली जा रही है जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है और इस प्रकार की अनियामित्ता आने वाले समय में ग्राम पंचायत के साथ ही उन ग्रामीणों के लिए भी मुसीबत बनेगी जो आस लगाए बैठे हैं कि नल,जल योजना से उनके घर तक समय-समय पर जल पहुंचेगा। बात करें बिछाई जा रही पाइपलाईन की तो फोटो में आप देख सकते हैं कि पूरा कार्य जेसीबी मशीन से होने के बावजूद भी पाइपलाईन को कितना ऊपर डाला जा रहा है। नियम अनुसार इसकी गहराई एक से डेढ़ मीटर के बीच में होनी चाहिए जो कि नहीं है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कार्य में भारी अनियामित्ता बरती जा रही है जो आने वाले समय में परेशानी का सबक बनगी। वहीं योजना अंतर्गत बन रही पेयजल की टंकी जो विगत ढाई से 3 महीने पूर्व ही शुरू हो चुकी थी लेकिन आज दिनांक तक उसके सिर्फ पिलर ही खड़े किए गए हैं बाकी कार्य अधर में लटका हुआ है जो शायद ही पूरा हो पाएगा।

क्या धोंस-धपस, आपसी झगड़ा करवाकर ही पूरी होगी योजना...?

पिछले अंक में समाचार प्रकाशन के बाद ठेकेदार इस तरह से बोखलाया है कि, उसने अपने कर्मचारियों के द्वारा गांव में फूट डालकर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा कर धोंस-धपस कर अपना कार्य पूरा करने की कोशिश की। वहीं कई किसानों ने गूंज को बताया है कि, उन्होंने कई बार कर्मचारियों से कहा कि हमारी पाइपलाईन फूट गई है उन्हें सुधार कर दो। जिनमें सिर्फ उन्हीं किसानों की बातें ठेकेदार कर्मचारियों ने सुनी जिनके साथ उनके व्यवहार घर जैसे थे, उन लोगों की बात एक भी नहीं सुनी गई जो या तो गांव में रहते नहीं है, कहीं काम पर गए हुए हैं या पेटलावद में काम करते हैं जो हर समय अपने घर पर नहीं रह सकते। स्वाभाविक है कि, उन्हें नहीं पता होगा उनकी पाइपलाईन कब फुट गई, कहां फटी और ठेकेदार कर्मचारियों ने बिना किये ही उसको दोबारा बुर दिया। ऐसे में जब शिकायत होती है ठेकेदार कर्मचारियों के साथ बहस होती है तब वह अपने निजी संबंध वाले दोस्तों को कहकर वाद विवाद करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं और अपना काम पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं।

शिव महापुराण का पंच कुंडी यज्ञ के साथ समापन

माही की गूंज, सारंगी।

ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर संगीत मय शिव महापुराण कथा का वाचन देपालपुर के पंडित गोपाल कृष्ण जी गोस्वामी के द्वारा किया गया। कथा समापन पर पंडित जी ने सभी शिव भक्तों को रुद्राक्ष एवं बिल पत्र व्यास पीठ से अपने हाथों से वितरित किए। प्रतिदिन कथा में पंडित जी द्वारा विस्तार पूर्वक शिव महापुराण कथा का महत्व बताया गया। इन सात दिनों में शिव महापुराण कथा में बारह ज्योतिर्लिंग, शिव पार्वती विवाह, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के साथ देवताओं का वर्णन सुनाया।

पंडित जी ने बताया, सत्संग में जाकर कथा सुनकर पुण्य लाभ लेना चाहिए। शिव महापुराण कथा पूर्ण होने पर पंच कुंडी यज्ञ में शिव भक्तों ने आहुतियां देकर धर्म लाभ लिया। इन सात दिनों में शिव भक्तों ने कथा पंडाल में पहुंचकर कथा सुनकर धर्म लाभ लिया। प्रतिदिन महाप्रसादी का वितरण अलग-अलग शिव भक्त द्वारा लाभ लिया गया। महाआरती एवं प्रसादी का वितरण किया गया। कथा समापन के पश्चात पंडित जी को रथ में बिठा कर ढोल, बैंड बाजे के साथ पूरे ग्राम में भव्य जुलूस निकाला गया एवं पंडित जी का स्वागत किया गया।

आयोजक समिति ने सभी शिव भक्तों का आभार माना।

जल में जीवन योजना पर ग्रहण: कस्बे में पाइपलाइन तक नहीं डाली गई

जहां पाइपलाईन बिछाई नल कनेक्शन हेतु स्टेंड भी लगे पर वहां जल प्रदाय नहीं

माही की गूंज,आम्बुआ।

केंद्र शासन की महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत घर-घर नलों के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना है। आम्बुआ में इस योजना का बंटाधार विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों ने मिलकर कर दिया। शिकायतों पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जिस कारण वह भी भाग गया और जवाबदार बैठे-बैठे बगैर योजना कार्य स्थल के निरीक्षण के खाना पूर्ति कर ऊपर तक ठीक है कार्य प्रगति पर है, पूर्ण हो गया है आदि की फाइल भेजने में मशगूल है। वही जनता इस भीषण गर्मी में सुखे कंठ योजना की विफलता के नजारे देखने को मजबूर है।

जैसा की विदित है देश के प्रधानमंत्री तथा केंद्र शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में पूर्व में किसी ने सोचा भी नहीं होगा वह योजना है ÷जल जीवन मिशन÷ । इस योजना के तहत देश के प्रत्येक गांव फलियों मोहल्लों तक ही नहीं अपितु प्रत्येक घर के दरवाजे तक नलों के माध्यम से पेयजल प्रदान किया जाना है। योजना पर विगत वर्षों से कार्य चल रहा है अलीराजपुर जिले के आम्बुआ में इसी योजना के तहत कस्बे से 2 किलोमीटर दूर कालादगड़ा नामक स्थान पर ऊंची पहाड़ी पर एक टंकी का निर्माण कराया गया टंकी तक जल पहुंचाने हेतु लगभग 8 ट्यूबवेल का खनन कराया गया तथा सभी में विद्युत मोटरे डाली गई टंकी स्थल से ग्रामीण क्षेत्र कालादगड़ा, समदनी फलिया, चौगड़ी फलिया, पटेल फलिया तथा फुलझड़ी एवं आश्रम फलिया आदि में पाइपलाईन बिछाकर नल कनेक्शन तथा नलों के स्टैंड बना दिए गए। मगर आम्बुआ का कस्बा क्षेत्र छोड़ दिया गया जहां पाइपलाईन नहीं डाली गई। कार्य में ठेकेदार ने घोर लापरवाही की घटिया कार्य किया योजना समय पर पूर्ण नहीं करने आदि की शिकायतों पर ठेकेदार जो कि गुजरात प्रांत का था को ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में डाल दिया गया। जिस कारण वह भी काम अधूरा छोड़कर विभागीय उदासीनता तथा मिली भगत के कारण भाग गया। जल प्रदाय नहीं होने से नागरिक परेशान है। नलों के स्टैंड पर भेड़ बकरियां जानवर बांधे जा रहे हैं। घटिया निर्माण के कारण नल स्टैंड उखड़ कर जमीन पर गिर गए।

जल जीवन मिशन की शिकायत आम्बुआ पत्रकार संघ द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को अवगत कराया गया। जहां बताया गया की जांच की जा रही है, ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही बताया, कस्बे के लिए अलग से टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है या फिर नई पाइपलाईन को पुरानी पाइपलाईन से जोड़ दी जाएगी। यानी कि कस्बे में पाइप तथा पाइपलाईन बिछाने का जो कार्य जल जीवन मिशन के ठेकेदार को कार्य योजना की स्वीकृति के अनुसार करना था वह न करा कर यहां पर होने वाले खर्च का बन्दरबाट किया जाने पर विचार किया जा रहा है या कर भी दिया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर जिला स्तर पर मिशन की समीक्षा तो की जा रही है मगर कार्य स्तर पर कार्य हुआ या नहीं इसे देखने कोई नहीं जा रहा है। आम नागरिको व ग्रामीण से कोई नहीं पूछ रहा कि उन्हें पानी मिल रहा है या नहीं नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। स्थिति ऊंट पर बैठकर बकरियां चराने जैसी हो रही है और जनता सूखे कण्ठ पानी का इंतजार कर रही है या जहां तहां से खरीद कर काम चला रही है। मगर आगे मिशन भीषण गर्मी में क्या होगा? यह विचारणीय होगा।

सड़क बनाने में अतिक्रमण बाधा बना कार्य नहीं हो पा रहा

कार्य रुकने के कारण मार्ग पर कीचड़ पसरा

माही की गूंज, आम्बुआ।

समीप ग्राम बोरझाड़ में ठेकेदार द्वारा बोरझाड़ से तलावद तक का सड़क मार्ग जो कि विगत वर्ष से निर्माण किया जा रहा है। वह वैसे भी कछुआ चाल से हो रहा है जैसे तैसे कार्य पूर्ण हो जाए तो आवागमन में सुविधा मिलने लगे मार्ग का काम बोरझाड़ आबादी क्षेत्र में किया जा रहा है। जिसके लिए सड़क किनारे किया गया बेतहाशा अतिक्रमण हटाना जरूरी है इसके नहीं हटने से कार्य होना असम्भव लग रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार बोरझाड़ तलावद कानाकाकड़, भाण्डाखापर मार्ग जो की झाबुआ मार्ग को जोड़ता है तथा समय पैसा और डीजल पेट्रोल की बचत करता है। कारण की यह कम दूरी का मार्ग है। जोबट-उदयगढ़ होकर जाने में दूरी अधिक होने से समय व पैसा आदि की हानि होती है। यह सड़क मार्ग विगत लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय से बनाया जा रहा है। यह जितना बनता है बनने में देरी के कारण बना हुआ मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के कारण तथा घटिया निर्माण के कारण उखड़ता भी जाता है। पता चला है कि, मार्ग अलग-अलग निर्माण एजेंसियों ठेकेदारों द्वारा बनाया जा रहा है। अब इस मार्ग का कार्य ग्राम बोरझाड़ में बाजार क्षेत्र यानी की आबादी क्षेत्र में हो रहा है जहां पर स्कूल के सामने से लेकर बस स्टैंड तक दोनों किनारो पर अतिक्रमण पसरा है। सामने की ओर जो आबादी बस्ती है तथा अधिकांश होटल किराना आदि का व्यवसाय करने वाले हैं ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है। ठेकेदार तथा प्रशासन स्तर पर उन्हें कई बार चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण यह निर्माण कार्य करने में परेशानी के चलते कार्य में बाधा आ रही है। इधर ठेकेदार द्वारा पूराना सीसी रोड खोदे जाने के समय नल जल योजना के पाइप तोड़ दिया जाने से पानी सड़क पर फैल कर कीचड़ कर रहा है। जिससे वाहन चालक तथा राहगीर परेशान हो रहे हैं। इसी मार्ग पर पुनः आबादी क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण के साथ-साथ नाली निर्माण भी होना है ताकि वर्षा का पानी सड़क पर ना फैल कर नाली में जा सके।

संपादकीय

सुलगते जंगल

हिमालयी क्षेत्र पूरे देश के मौसम का नियामक है। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा-जमुना जैसी अनेक सदानीरा नदियां देश की जीवनधारा को सींचती हैं। ग्लेशियरों वाले इलाके में जहां जलभंडार हैं, वहीं समृद्ध जैव विविधता भी। ऐसे में गंगा-जमुना के मायके के जंगलों से लगातार आग के समाचार परेशान करते हैं। मई के पहले सप्ताह में ही आग लगने की करीब साढ़े नौ सौ घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जिसमें करीब बारह हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को अग्निकांड से नुकसान हुआ। पांच लोगों के मरने की भी खबर है। यूं हर वर्ष उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें आती हैं। यह सिलसिला मार्च के अंत से शुरू होकर मई तक चलता है। लेकिन इस बार यह संकट ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। कई जनपदों में दृश्यता में कमी आई है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों व भौगोलिक जटिलताओं के चलते वनों का धधकना जारी है। काबू पाने के लिये वायुसेना व एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। यह एक हकीकत है कि जंगलों के धधकने में मानवीय हस्तक्षेप कहीं न कहीं जरूर होता है। माना जंगलों में गिरने वाली पत्तियों व घास का समय रहते निस्तारण न होने से ज्वलनशीलता तो होती है, लेकिन आग इंसानी लापरवाही या साजिश से ही लगती है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि नवंबर 2023 से अब तक करीब पौने चार सौ वन अपराधों के मामले पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें साठ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। इस बात को उत्तराखंड का वन विभाग भी स्वीकार करता है कि 95 फीसदी अग्निकांड के मामलों में मानवीय दखल जिम्मेदार होता है। जिसमें लापरवाही के साथ-साथ इरादतन लगाई गई आग भी शामिल है। इस बार जहां आग लगाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहीं विभाग के लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ भी लापरवाही के चलते कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल, अग्निकांडों के बाद कार्रवाई फॉरेस्ट एक्ट व वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी संपत्ति नुकसान क्षतिपूर्ति कानून के तहत भी कार्रवाई होगी। इस संकट को देखते हुए एनडीआरएफ व वायुसेना के हैलिकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। वहीं आईआईटी रुड़की की मदद से कृत्रिम बारिश के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर साल जलने वाले सैकड़ों हेक्टयर वनों को आग से बचाने के लिये स्थायी उपायों की जरूरत महसूस की जा रही है। हमें वर्ष 2021 में हुए अग्निकांडों से सबक लेना चाहिए, जब आग लगने की करीब 2813 घटनाओं में करीब चार हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को क्षति पहुंची थी। अग्निकांडों में आठ लोग मारे गये थे। रोचक तथ्य यह है कि कोविड-19 के दौर में मानवीय आवाजाही कम होने से आग लगने की सबसे कम घटनाएं हुई थीं। दरअसल, सरकारों की प्राथमिकता में पर्यावरण व वन संरक्षण शामिल ही नहीं हो पाया है। वनों के संरक्षण के लिये बजट बहुत कम है और आग बुझाने के पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। पिछले दिनों अग्निकांड की घटनाओं के दौरान वनकर्मियों की ड्यूटी चुनाव के लिये लगाने पर भी सवाल उठे। इसके अलावा एक बात तो तय है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते वातावरण में तापमान बढ़ने से भी आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। हमें बढ़ते तापमान के साथ प्रकृति संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना होगा। राज्य सरकार को एक सदी से अधिक समय से चली आ रही उस वन पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना होगा, जो वन संरक्षण में सदैव सहायक रही है। साथ ही चीड़ के उन पेड़ों के बारे में भी सोचना होगा, जिन्हें अंग्रेज बाहर से लाए थे और उसकी सूखी पत्तियों की आग भड़काने में बड़ी भूमिका होती है। दरअसल, पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में कृषि व पशुधन के लिये घास-पात का उपयोग न होने से भी जंगलों में ज्वलनशील स्थितियां बनी हैं। वहीं वन कानून सख्त होने से ग्रामीणों के हितों की अनदेखी के चलते उनकी वनों के प्रति उदासीनता भी बढ़ी है। निस्संदेह, जंगलों की आग वन विभाग ग्रामीणों के सहयोग के बिना नहीं बुझा सकता।

जन जागरूकता रोकेगी चुनावी स्तर में गिरावट

वे तीनों पढ़े-लिखे हैं। कहना चाहिए उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उनमें से दो पत्रकार हैं और तीसरा एक बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन में उच्च अधिकारी। इन तीनों में हो रही बातचीत देश में चल रहे चुनाव के बारे में थी और तीनों इस बात पर चिंता प्रकट कर रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश होने का दावा करने वाले देश में चुनाव का स्तर इतना नीचा क्यों होता जा रहा है।

देश में मतदान का तीसरा दौर पूरा हो चुका है। बाकी के चार दौर भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। चार जून को मतदान का परिणाम भी सामने आ जायेगा। तब मतदाता तय कर लेगा कि किसको सत्ता में बिठाना है और किसे विपक्ष की भूमिका देनी है। चुनाव जनतंत्र का उत्सव ही नहीं होते, जनतंत्र की प्राणवायु भी होते हैं। और उन तीन जागरूक नागरिकों की चिंता भी इसी बात को लेकर थी कि देश में चुनाव प्रचार का घटता स्तर इस प्राणवायु में ज़हर घोल रहा था। ज़हर घोलने जैसे शब्द कुछ कठोर लग सकते हैं, लेकिन चुनाव-प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ-साथ जिस तरह चुनाव प्रचार की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उसे देखकर देश के बुद्धिजीवियों के आकलन को अनदेखा करना भी ग़लत होगा। सही यह भी है कि आम मतदाता भी इस गिरते स्तर से स्वयं को कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

भाजपा में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। इसकी तुलना में विपक्ष बहुत पीछे था। कारण कुछ भी रहे हों, विपक्ष की यह स्थिति भाजपा को अति विश्वास की तरफ ले जा रही थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के प्रचार-महारथी बड़े विश्वास के साथ 'अब की बार चार सौ पार' का नारा लगा-लगवा रहे थे।

यह नारा तो अब भी चुनावी-सभाओं में सुनाई दे जाता है, पर आवाज में एक अविश्वास भी झलकने लगा है। जिन तीन बुद्धिजीवियों की बात प्रारंभ में की गई है, उनका यह भी मानना है कि समूचे चुनाव प्रचार में अब एक अंतर्धारा भी प्रवाहित हो रही है। और यह 'तथ्य' सत्तारूढ़ पक्ष के नेतृत्व को भी पता लग रहा है। शायद यही कारण है कि उसके चुनावी सिपहसालार प्रचार के पुराने हथियारों को उठाने की आवश्यकता महसूस करते लग रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री की भाव-भंगिमा और शब्दावली भी इसी ओर इशारा कर रही है। फिर से 'शहजादा' शब्द उन्हें ज़रूरी लगने लगा है। इस बार कांग्रेस भी कुछ ऐसी शब्दावली काम में लेने की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस की एक नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के शहजादा-वार के जवाब में 'शहंशाह' शब्द को तीर बनाया है।

शहजादा और शहंशाह के इस मुकाबले में चुनाव के सही मुद्दे उपेक्षित होते लग रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के नेतृत्व द्वारा वर्षों पुरानी बातों को फिर से सामने लाना भी इसी बात का संकेत है कि सत्तारूढ़ दल को अपने किये पर उतना भरोसा नहीं लग रहा, जितना पिछली सरकारों के अनकिये का लाभ मिलने पर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अल्पसंख्यकों का 'पहला अधिकार' वाला अठारह साल पहले वाला बयान प्रधानमंत्री मोदी को अब फिर उपयोगी लग रहा है। इसी तरह 'तुष्टीकरण' वाली बात भी फिर जोर-शोर से उठायी जा रही है। राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस के नेतृत्व को घेरने की कोशिश भी फिर से शुरू हो गयी है। विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस को, राम विरोधी बताकर एक बार फिर हिंदुत्व को हथियार बनाने की नीति का पालन हो रहा है। कुछ बीजेपी समर्थक तो यह भी कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होता तो कुछ अधिक चुनावी लाभ मिलता!

देश की सारी चुनावी-राजनीति इसी लाभ को केंद्र बनाकर चल रही है। हमारे राजनेता यह भूल रहे हैं कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए होनी चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि सत्तारूढ़ दल अपने दस साल के कार्यकाल का हवाला देकर फिर से मतदाता का समर्थन मांगता, पर हो कुछ और ही रहा है। हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के परिणामस्वरूप ही आज के प्रधानमंत्री को काम करने में दिक्कत हो रही है। चुनाव प्रचार के स्तर का लगातार गिरना भी यही दर्शाता है कि हमारी आज की राजनीति सही मुद्दों को अनदेखा कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोज़गारी जैसे ज़रूरी मुद्दों की जगह हमारी राजनीति सांप्रदायिकता का सहारा लेने के लिए जैसे बाध्य हो रही है। संप्रदाय विशेष को 'घुसपैठिए' और 'बच्चे पैदा करने वाली मशीन' बताने वाले एक घटिया राजनीति का उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुसंख्यकों की संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांटने की 'साजिशों' की बात करना भी हमारी राजनीति के हल्केपन को ही उजागर करता है।

बहरहाल, यहीं इस बात को भी रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि भाजपा के चार सौ पार वाले नारे ने अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के मन में एक डर भी पैदा कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि लोकसभा में चार सौ से अधिक का बहुमत पाकर भाजपा संविधान को बदलने की स्थिति में आ सकती है। यह सही है कि भाजपा का शीर्ष-नेतृत्व बार-बार इस बात को दुहरा रहा है कि संविधान नहीं बदला जायेगा, और न ही पिछड़ों के अधिकार छीने जाएंगे, लेकिन भाजपा के ही कई नेता इस आशय की बात करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ऐसे में मतदाता का शंकालु होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं के चुनाव प्रचार में आ रही गिरावट भी चिंता का विषय होनी चाहिए। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव आयोग के समक्ष इस गिरते स्तर की शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मिली ऐसी शिकायत को लेकर प्रधानमंत्री के दल के अध्यक्ष को आगाह किया है। ऐसी कार्रवाई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी हुई है। यह भले ही एक प्रकार का संतुलन बनाने की कोशिश हो, पर निश्चित रूप से यह चिंता की बात है कि हमारी राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। सारे प्रावधानों के बावजूद हमारे राजनेता घटिया भाषा और घटिया भावों के सहारे राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। विडंबना यह भी है कि ऐसे घटिया आचरण को रोक पाने में संबंधित एजेंसियां विफल सिद्ध हो रही हैं। हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत पर चुनाव आयोग ने इन दोनों से पूछताछ के बजाय इनके दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा!

विश्वनाथ सचदेव

चुनाव प्रचार का यह हल्का स्तर हमारे मीडिया की करनी पर भी सवाल उठाता है। होना तो यह चाहिए था कि ऐसे आचरण की आलोचना हमारा मीडिया करता, पर हो यह रहा है कि मीडिया ऐसी बातों को प्रचारित करने में मददगार सिद्ध हो रहा है! इस घटिया राजनीति का विरोध होना ही चाहिए। और यह विरोध जागरूक मतदाता को ही करना है। मतदाता की जागरूकता जनतंत्र की सफलता-सार्थकता की पहली शर्त है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई के तीन बुद्धिजीवी जिस अंतर्धारा की बात कर रहे थे उसके मूल में यह जागरूकता प्रवाहित हो रही है।

कृषि बजट वृद्धि दिलाएगी 'अरबपति राज' से मुक्ति

देविंदर शर्मा

भले ही वह विशुद्ध राजनीतिक कारणों से हो, भारत में धन के पुनः बंटवारे पर बहस बेहद महत्वपूर्ण है और वक्त की जरूरत भी। मुट्ठीभर अमीरों के हाथों में धन के केंद्रित होने की अप्रिय स्थिति की वजह से 'अरबपति राज का उदय' हुआ, जैसा कि पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब ने इसे नाम दिया है। यह कथित 'अरबपति राज' निश्चित रूप से उद्यमशीलता के प्रति एनिमल स्पिरिट यानी जिंदादिली या भावनात्मक जोश के उजागर होने के कारण नहीं है लेकिन यह इस बात का दुखद परिदृश्य है कि कैसे कुछ लोगों के हक में आर्थिक नीतियों और संसाधनों को अनावश्यक रूप से सौंप दिया गया।

जॉन मेनार्ड केंज ने अपनी पुस्तक 'द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी' (1936) में 'एनिमल स्पिरिट्स' की व्याख्या उस असाधारण मानवीय व्यवहार के रूप में की है जो अनिश्चयपूर्ण दशाओं में निवेशकों को वित्तीय निर्णय लेने को प्रेरित करता है। पर संभवतया केंज को यह अहसास नहीं हो कि बहुसंख्यक आबादी को ऐसे ही अवसर से वंचित रखना असल में लाखों फूलों के खिलने के लिए जरूरी उत्साह और 'एनिमल स्पिरिट' को नष्ट करना है।

किसी भी मामले में, जहां केंज गलती पर हैं, वह यह है कि मुट्ठी भर अरबपतियों का होना महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी संपत्ति एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई उस मददगार प्रणाली के बल पर बढ़ती रहती है, जिसमें टैक्स छूट, बैंक ऋण बट्टे खाते में डालना और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। बल्कि उसी के समान संसाधनों को एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए भी खर्च करना होगा जहां खुशी और संतुष्टि का राज हो। आखिरकार, संसाधन सीमित हैं और यह देखना अहम है कि इन्हें कैसे वितरित किया जाता है। शायद यही वजह है कि नॉर्डिक क्षेत्र के 4 देशों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड बेहद अच्छा कर रहे हैं और खुशहाली की सूची में लगातार अव्वल रहते हैं।

एक दिन टीवी पर पैनल चर्चा के दौरान मुझसे पूछा गया कि यदि धन का पुनः वितरण करना पड़ा तो सरकार क्या कर सकती है। मेरा जवाब था कि लगता नहीं है कि अमीरों का धन छीनकर गरीबों में बांटने का कोई विचार हो। चाहिये क्या कि नीतियों और दृष्टिकोणों में पुनः बदलाव कर यह यकीनी बनाना होगा कि उनका लाभ देश के किसी भी हिस्से में मौजूद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

मेरा पहला सुझाव होगा यह यकीनी बनाना कि सालाना बजट का 50 फीसदी कृषि को दिया जाना चाहिये जो साल 2024 के लिए 47.66 लाख करोड़ है। जो मोटे तौर पर देश की आधी आबादी बनती है। खेती में आबादी का इतना बड़ा हिस्सा लगे होने के बावजूद वर्तमान में इस क्षेत्र को बजट आवंटन में 3 फीसदी से भी कम प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि उचित निवेश नहीं करते।

ऐसे देश में जहां सिर्फ 21 अरबपतियों के पास 700 मिलियन से अधिक की धन-संपत्ति है, और जहां 64.3 प्रतिशत आबादी से 64.3 प्रतिशत जीएसटी आता है और शीर्ष 10 फीसदी से केवल 3-4 प्रतिशत ही आता है। जहां पहले से ही काफी निवेश किया जा चुका हो, वहां संसाधनों को लगाने में कोई आर्थिक समझदारी नहीं। इसके विपरीत, वित्तीय संसाधनों का समान और न्यायसंगत तरीके से पुनर्वितरण करना नितांत आवश्यक है। खेती में लगी 50 फीसदी आबादी को आर्थिक संसाधनों में उसके जायज हिस्से से क्यों वंचित किया जाए, जबकि लगातार सरकारें साल-दर-साल औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर बजटीय प्रावधान करती रही हैं।

मुझसे सवाल किया गया कि खेती से आमदन पर कोई टैक्स नहीं है, और वह इस सेक्टर के लिए बड़ी वित्तीय मदद है। वास्तव में, पैनल चर्चा में शामिल एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने यहां तक पूछा कि अमीर किसानों पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, जबकि उन्हें यह अहसास नहीं था कि भारत में केवल 1 प्रतिशत कृषक समुदाय के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और कृषक परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण, 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शेष 99 प्रतिशत कृषक समुदाय की औसत आय लगभग 10,000 रुपये प्रति माह है। विडंबना है कि कॉर्पोरेट अर्थशास्त्रियों को कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट के बारे में बहुत कम जानकारी है, और वे अभी भी पुराने जमाने की आर्थिक सोच पर चलते हैं जो किसानों को शहरों में प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर आधारित थी।

एक अन्य पैनल चर्चा में, मैंने बताया कि कैसे कॉर्पोरेट कंपनियां पिछले दस वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये के बैंक राइट-ऑफ लेकर गयी हैं, और इसके साथ सितंबर 2019 से हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये की टैक्स कटौती दी गई है। इतना कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के साथ 'समझौता' करने का निर्देश दिया है, जिन पर 3.45 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, और जिनके पास भुगतान करने के लिए संसाधन हैं लेकिन वे परवाह नहीं करते हैं। जिस तरह से किसानों को बैंक की किस्तें चुकाने में असमर्थ होने के चलते जेल में डाल दिया जाता है, उसी तरह 16,400 जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को भी जेल की सजा होनी चाहिए थी। इसके बजाय उन्हें आसानी से छोड़ दिया गया। इस तरह के भारी राइट-ऑफ से अमीरों को जाहिर तौर पर राहत मिलती है। उनकी जीवनशैली हमेशा पूर्ववत चलती रहती है। यदि किसानों को भी ऐसी राहत राशि दी जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे भी अपनी 'एनिमल स्पिरिट' का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।

मई 1996 में जब वाजपेयी सरकार ने पहली बार शपथ ली, तब नई सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले आर्थिक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए बुलाई गई अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में मेरा सुझाव था कि कृषि में संलग्न 60 प्रतिशत आबादी के लिए वार्षिक बजट का 60 प्रतिशत प्रदान किया जाए, यदि विचार सत्ता विरोधी लहर से बचने का हो। (उस समय जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि का था)। यह बात अब भले ही भुला दी गई हो लेकिन वाजपेयी सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए समर्पित करेगी। यह एक ऐसा परिवर्तन कारी कदम होता जिसकी देश को तलाश थी। जहां तक मुझे याद है यह पहली बार था कि संसाधनों के पुनर्वितरण का प्रयास किया गया था। दुर्भाग्य से, सरकार 13 दिन में ही गिर गयी। यदि केवल वाजपेयी सरकार कायम रहती, कृषि पर बजट आवंटन में 60 फीसदी लगाने के नीतिगत फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था यकीनी तौर पर पुनर्जीवित होती, और उसके असर से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी आती। उसके चलते अब तक सबका साथ सबका विकास यकीनी बनता।

अब जबकि नव-उदारवाद हांफ रहा है, और अपने अंतिम चरण में है, ऐसे में धन के पुनः वितरण की किसी भी बात को अर्थशास्त्रियों के शासक वर्ग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनसे घबराएं नहीं, बल्कि खड़े हो जाओ और अपनी राय से अवगत कराएं। और विश्वास रखें कि धन का पुनः वितरण एक विचार है जिसका समय अब आ गया है।

के नाम पर नही काम के नाम पर चुनिए

हम कलम घसीटने वालों के पास मुफ्त में देने के लिए अन्न नहीं है लेकिन तजुर्बे हैं,सलाह- मशवविरे हैं, जो हम लगातार देते रहते है। अठारहवीं लोकसभा के लिए तीसरे चरण के मतदान के बाद चौथे ,पांचवें,छटवें और सातवें चरण में मतदान करने वालों को हमारी सलाह है कि वे राम के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर मतदान करें और जो राम के नाम पर भिक्षाटन कर रहा हो उसे या तो राम के पास ही माला जपने के लिए भेज दें या फिर उससे कहें की वो काम करे।

देश की जनता राम को अपना आराध्य मानती है और राम के नाम पर लगातार उदारता दिखाकर मतदान भी करती आयी है किन्तु अब राम जी की कृपा से जनता जाग गयी है। जनता को समझ में आ गया है कि राम को तो वोट की जरूरत है ही नहीं। वे तो पहले से राजा राम है। वोट तो उनके नाम पर राजनीतिक ठगी करने वालों को चाहिए। हरियाणा में दल-दल से बाहर खड़े होकर दलदल की सरकार का समर्थन करने वाले तीन निर्दलीय विधायकों को सबसे पहले ये समझ में आया है और उन्होंने राम के नाम पर बनी नकली राम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब हरियाणा में या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर नए चुनाव होंगे। राम के नाम पर खरीद-फरोख्त की गुंजाइश अब लगभग बची नहीं है।

हरियाणा की जनता और नेता राम के साथ ही कृष्ण की भी सुनते है। असली महाभारत तो हरियाणा में ही हुआ था। यहां के लोग रामायण के साथ ही गीता के उपदेशों के बारे में भी जानते हैं। शायद इसीलिए भाजपा को समर्थन दे रहे तीन निर्दलीयों ने सरकार से समर्थन वापस लेते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का एलान कर दिया है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ निर्दलीय विधायक दादरी से सोमबीर सांगवान, पूंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंधर ने कांग्रेस के समर्थन का एलान किया है।

देश में जब रामनाम की खुली लूट चल रही थी तब भी 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 सीटों में से भाजपा ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में असफल रही थी। वहीं, इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी के दस विधायक बने थे। सात निर्दलीयों ने भी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 31 सीट तो इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में एक एक सीट आई थी। इस स्थिति में भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन किया और करीब साढ़े चार साल तक प्रदेश में सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस की आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने से खाली हुई और वहां उपचुनाव में उनके बेटे ने जीत दर्ज की और भाजपा के प्रदेश में 41 विधायक हो गए। वहीं, कांग्रेस के पास तीस विधायक रह गए।

पिछले दस साल में भाजपा ने राम के नाम पर अनेक राज्यों की चुनी हुई सरकारें गिराईं, दल-बदल कराया, पार्टियों को तोड़ा किन्तु ये पहला मौक़ा है जब खुद भाजपा की सरकार टूट रही है। यानि जो तकनीक भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए अब तक इस्तेमाल करती आ रही थी, उसी तकनीक से उसे हरियाणा में सत्ता से बेदखल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए हुए तीसरे चरण के मतदान के दिन ही भाजपा को ये उपहार मिला है। इस घटना से हरियाणा को जो कष्ट झेलना पड़ेंगे वे तो अलग हैं लेकिन अब भाजपा को चार सौ पार करने के लिए फिर से प्रभु राम की शरण में जाना पड़ेगा। कोई दूसरा पुलवामा भी भाजपा की मदद कर सकता है, लेकिन आज का समय और भगवान राम तो उसके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं।

आपको याद दिला दूँ कि हरियाणा में जजपा पांडवों की तरह भाजपा से लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में बने रहने के लिए मात्र 2 सीटें मांग रही थी,किन्तु हरियाणा में कौरव बनी भाजपा ने जजपा को ठेंगा दिखा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही 12 मार्च को हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन टूट गया। भाजपा को मजबूरी में राज्य में मुख्यमंत्री बदलकर मनोहर लाल खटटर की जगह नबाब सैनी को लाना पड़ा। जजपा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा के पास अपने 41, छह निर्दलीयों और एक हलोपा विधायक का समर्थन था। जजपा के कुछ विधायक भी भाजपा के साथ आते दिखाई दिए, लेकिन विहिप जारी होने के कारण सदन से बाहर चले गए और ध्वनि मत से सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खाले हुए हैं।

मोशा की जोड़ी मुमकिन है कि जोड़तोड़ से हरियाणा की सरकार एक बार फिर बचा ले किन्तु अब पूरा देश भाजपा की हकीकत समझ गया है। अब भाजपा के सामने हरियाणा से ज्यादा दिल्ली की सरकार को बचाने की चुनौती है। राम जी के नाम पर अब देश की जनता भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। अब भाजपा को राम के नाम पर नहीं बल्कि अपने काम पर वोट मांगना चाहिए अन्यथा राम नाम सत्य साबित हो सकता है। मुझे भाजपा का जाना अच्छा नहीं न लगेगा क्योंकि बेचारी भाजपा ने राम के नाम पर देश में बहुत पापड़ बेले हैं। जनता को खिलाकर भरमाया है। किन्तु यदि जनता काम पर वोट देने की आदत डालकर कोई फैसला करती है तो मै क्या पूरा देश, हमारी भारत माता, हमारा लोकतंत्र सुखानुभूति करेगा। क्योंकि हमारे देश में 1980 के पहले राम-श्याम के नाम पर वोट मांगने की परम्परा नहीं है और फिर राम-श्याम के नाम पर वोट मांगे भी क्यों जाएँ?

राकेश अचल

हरियाणा के निर्दलीय विधायकों की ही तरह राम जी करें कि हमारा केंचुआ भी नींद से जागे और बदजुबानी करने वालों को केवल नोटिस देकर ही न छोड़े बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रमाणित करे की उसके पास भी रीढ़ की हड्डी है। केंचुआ हो या न्यायपालिका या संसद जिसने भी, जब भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया है लोकतंत्र का स्वास्थ्य सुधरा है। भारत का लोकतंत्र कुछ कांग्रेस ने बीएमआर किया था और बचा-खुचा भाजपा ने कर दिया। जनता ही जो लोकतंत्र को बचा सकती है। हम जनता में फर्क नहीं करते। लोकतंत्र बचाने कि लिए उस 85 करोड़ जनता की भी जरूरत है जो पांच किलो अनाज कि लिए सरकार की मोहताज है और उस जनता की भी जो भक्ति करते-करते अंधभक्ति की शिकार हो गयी थी। राम सबकी रक्षा करें।

परिवारवाद को लेकर मुख्यमंत्री और विधायक ने साधा एक -दूसरे पर निशाना

माही की गूंज, रतलाम।

मध्य प्रदेश की रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट पर अब परिवारवाद की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर परिवार वाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस लंबे समय से वही पुराने चेहरों को मैदान में ला रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को कांग्रेस को परिवारवाद से जोड़ते हुए जमकर हमला बोला। इस आरोप पर कांग्रेस भी अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने पलटवार करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया है।

गांधी परिवार पर सीएम यादव का तंज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सैलाना में आम सभा के दौरान कहा कि, देश की आजादी के बाद गांधी परिवार ने लगातार कई वर्षों तक राज किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 17 वर्ष, राजीव गांधी ने 5 वर्ष और मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी ने 10 वर्ष तक देश में पीछे से सरकार चलाई। सीएम यादव ने कहा कि क्या पूरे देश और लोकतंत्र चलाने का ठेका गांधी परिवार ने ले रखा है?

सीएम यादव के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार

इस आरोप पर झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने पलटवार करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर भी परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि, अनीता नागर चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके पति नागरसिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए विक्रांत भूरिया ने कहा कि, अनीता नागर चौहान के परिवार में जनपद अध्यक्ष मौजूद हैं। वे खुद जिला पंचायत की 10 वर्ष से अध्यक्ष हैं। इसके अलावा परिवार में कई लोग समिति सहित कई और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। ऐसी स्थिति में क्या अनीता नागर चौहान को टिकट देकर मोदी सरकार और बीजेपी संगठन ने परिवार वाद को बढ़ावा नहीं दिया है...?

आदिवासी महिला दिया टिकट

मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला को टिकट देकर पूरे समाज का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि, वे 10 वर्ष से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसी स्थिति में वे क्षेत्र की समस्याओं को भलि-भांति जानती हैं। आपको यह भी बताते चले कि, जिस समय आदिवासी समाज को भुनाने के लिए सीएम आदिवासी महिला को टिकिट देने की बात कह रहे थे, शायद वह भूल गए थे कि झाबुआ-रतलाम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो यहां आदिवासी को ही टिकिट दिया जाता है चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो, भारत आदिवासी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो।

हर समस्या के निराकरण की गारंटी

रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर चौहान ने भी मंच से खड़े होकर कहा कि, मेरे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हाथ है, ऐसे में क्षेत्र की हर समस्या का निराकरण करने की गारंटी देती हूं।

हम देश में दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता चाहते है- मुख्यमंत्री

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर चुनावी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार सुबह प्रबुद्धजन संवाद में मंदसौर के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों से खुलकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मंदसौर स्थित अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन-पूजन भी किया। और महादेव से भोलेनाथ की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे, प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि की वर्षा हो, मानवता का कल्याण हो, की प्रार्थना की। उन्होंने सेवानिवृत न्यायाधीश रघुवीरसिंह चूंडावत से आइपीसी सहित कानून संबंधी प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हम देश में दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता चाहते है। भाजपा याने भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की जनता की पार्टी है। हमने सबको साथ लेकर काम करने की ठानी हुई है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि, जनता के एक-एक आदमी का कोर्ट से काम पड़ता है। पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए न्यायालयीन परिवर्तन चाहते है। चोर की गर्दन पकड़ने का काम पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने रिश्वतखोरों को उनकी जमीन दिखाई है। इसलिए पीएम मोदी को देश का चौकीदार कहा गया है। सबसे ज्यादा कानून की बात करने वाले दिल्ली वाले भाई साहब की स्थिति सबके सामने है। जेल में बंद मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए, लेकिन खुद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी का साफ कहना है न खाऊंगा और न खाने दूंगा।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि, मुखिया की जवाबदारी सबसे अधिक होती है। परिवार में कुछ भी होता है तो प्रतिष्ठा मुखिया की दांव पर लगती है। तो फिर दिल्ली के मुखिया अपनी जवाबदारी मानने को तैयार क्यों नहीं है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। चाहे बात देश के विकास की हो या राष्ट्र व जनता की सुरक्षा की हो। जीएसटी, नोटबंदी कोई छोटा मोटा काम है क्या? मोदीजी ने केवल देश की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाया और ऐसे बड़े निर्णय लिए। जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है।

सीएम ने कहा कि, पीएम नरेन्द्र मोदी का न खुद का मकान है और न जमीन है और न भारी भरकम बैंक अकाउंट। हर कोई अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं।

मोदी के नाम पर घर बैठे 2 बार जीत गए, क्षेत्र में नहीं किया कोई काम- कांग्रेस प्रत्याशी

माही की गूंज, मंदसौर।
साहिल अगवान

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मजबूत हो जाती है। यह बात बीजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी भी मान रहे हैं। मंदसौर के कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के मुताबिक उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर घर बैठे ही चुनाव जीत गए। इस बार वे कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं।

मंदसौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि, इस बार मंदसौर लोकसभा सीट की हवा बदली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि, भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी निष्क्रियता का लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है।

कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर

भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता

पीएम मोदी के नाम पर भाजपा को मिलती मदद

दिलीप गुर्जर ने कहा, दो बार भाजपा प्रत्याशी ने हर गांव जाकर वोट भी नहीं मांगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया। इस बार कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गुर्जर ने कहा कि, अफीम किसानों की कई बड़ी समस्याएं है। वे सीपीएस प्रणाली के जरिए खेती करना चाहते है।

कांग्रेस उम्मीदवार ने आगे कहा, इस प्रणाली को लागू करने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का स्तर बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव में काफी मदद मिल जाती है।

कांग्रेस को बता कर प्रचार नहीं करती भाजपा

कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि, पार्टी अपनी रणनीति के तहत प्रचार प्रचार करती है। कांग्रेस नेताओं को बता कर प्रचार करने नहीं जाती। मंदसौर के भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जीत दिलाने वाला है। यह बात सही है कि प्रधानमंत्री के नाम पर भाजपा सभी सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मत मिलते हैं।

खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह निलंबित

माही की गूंज, शाजापुर।

खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह के विरूद्ध अकोदिया थाना मण्डी में अपराध क्रमांक 68/24 धारा 279 एवं 304ए के तहत प्रकरण की कायमी हुई है। प्रकरण के सिलसिले में खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने, पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने, कार्यो के प्रति उदासीनता, अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने के कारण कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1966 के नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। गोविन्द पाल सिंह का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय शाजापुर रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मतदान करो और कटिंग पर डिस्काउंट पाओ

माही की गूंज, शाजापुर।

शाजापुर में एक सैलून संचालक ने अनोखी पहल शुरू की है। यह संचालक हैं जीवन वर्मा जो नई सड़क पर अपना सैलून संचालित करते हैं। चर्चा में जीवन वर्मा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में अब तक हुए दो चरणों में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, जो उन्हें कतई अच्छा नहीं लगा।

इसी के चलते उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वे भी जिला प्रशासन का सहयोग कर मतदाताओं को जागरूक करने की पहल करें। उन्होंने इसकी शुरूआत की और उन्होंने अपनी दुकान पर एक पम्प्लेट चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि 13 मई सोमवार को मतदान करके निशान दिखाओ और कटिंग पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट पाओ।

हर ग्राहक को करते हैं जागरूक

हेयर सैलून संचालक वर्मा ने बताया कि, एक अच्छी सरकार बने और हमारा देश तरक्की करे। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जिसके चलते वे अपने यहां आने वाले हर ग्राहक से कहते हैं कि गर्मी से न डरें, आप मतदान केंद्र जाइए। वहां आपको पानी, छांव सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आप अपने मताधिकार का उपयोग करें।

कैमरों से रखी जा रही जिले की 15 चेक पोस्ट पर नजर

माही की गूंज, रतलाम।

लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत चौथे चरण के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से चेक पोस्टों पर नजर रखी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम के निर्देशन में शहरी विकास अभिकरण कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में पांच कम्प्यूटर स्क्रीन पर सीमावर्ती चेक पोस्ट की हर गतिविधि देखी जाती है।

शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरुण पाठक ने बताया कि, जिले में बनाए गए चेक पोस्ट पर तैनात स्थैतिक निगरानी दलों के वाहनों पर भी जीपीएस लगाए गए हैं जिससे कि उनके मूवमेंट की मॉनिटरिंग संभव हो सकी है। जिले की विभिन्न सीमाओं पर बनाए गए 15 चेक पोस्ट में से प्रत्येक पर दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण के सातरुंडा में चेक पोस्ट बनाई गई है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सैलाना के अमरगढ़, कुंडा, बोरदा, सेरा, सज्जनपुरा, गड़ीकटारा, कुंदनपुर, अमरपुरा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा के आरटीओ बैरियर साकथली फंटा, सुखेड़ा, निपानिया फंटा, कोटडी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के भोजाखेड़ा फंटा, कलसिया फंटा, मजनपुरा में चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनके माध्यम से वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जाती है अपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है।

चौथे चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार 13 मई को मतदान होना है। इन आठ लोकसभा क्षेत्रों के 18 हजार 7 मतदान केन्द्रों पर सात मई से यह अभियान शुरू हो गया है। इसमें देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र शामिल हैं।

महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, मामला दर्ज

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में मंगलवार-बुधवार रात एक महिला को पीटने का मामला सामने आया है। घटना क्षेत्र के बसेड़ा की है। पुलिस के अनुसार, एक विवाहिता समाजिक कार्यक्रम के बाद घर लौटी थी। इस दौरान करीब आधा दर्जन महिला-पुरुषों ने महिला के साथ हाथ पैर पकड़ कर गंभीर मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए।

इसके बाद महिला को निवस्त्र कर दिया।

पीड़िता का आरोप है कि, आरोपियों ने उस पर उनकी लड़कियों को भगाने का झूठा आरोप लगाते हुए चौराहे पर निवस्त्र कर मारपीट की। पीड़िता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है।

पति और बेटे ने छुड़वाया

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि, राजू पुत्र माधु मीणा, माधु मीणा, बापू लाल, पारस मीणा और मदन, गुड्डी बाई, रुकमणी, शांति सहित अन्य ने मेरे साथ मारपीट की। अपशब्द कहकर निर्वस्त्र कर मारपीट करने लगे। बाद में पीड़िता के पति और बेटे ने आकर उसे छुड़वाया और दूसरे वस्त्र पहनाए। महिला ने गंभीर अवस्था में ही पुलिस थाने आकर मामला दर्ज कराया।

मामले की जांच जारी

मामले में डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया ने बताया कि, पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है। जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी आरोप महिला ने लगाए हैं उनकी जांच कर रहे हैं।

क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण, अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों को दिया नोटिस

माही की गूंज, शाजापुर।

लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के 5 क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना एवं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने किया। इस दौरान सहायक कलेक्टर शिवम यादव, जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत राजकुमार हलधर, तहसीलदार श्रीमती मधु नायक सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम शाजापुर शहर के मतदान केन्द्र क्रमांक 151 अम्बेडकर भवन महूपुरा एवं 160 कन्या प्राथमिक शाला भवन महूपुरा का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मतदाता पर्ची के वितरण की जानकारी बीएलओ से ली। इसी तरह मतदान केन्द्र क्रमांक 142 एवं 143 प्राथमिक शाला भवन पिपल्या गोपाल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने समुचित प्रकाश व्यवस्था करने तथा रेम्प सुधारने के निर्देश दिये। मतदान केन्द्र क्रमांक 231 अतिरिक्त कक्ष कन्या मावि पूर्वी भाग, 232 शाउमावि एवं 233 प्राथमिक शाला भवन रंथभंवर का निरीक्षण कर कलेक्टर ने मतदान केन्द्र क्रमांक 232 में रखी सामग्री को हटाने के निर्देश दिये। मतदान केन्द्र क्रमांक 301 प्राथमिक शाला भवन देंदला के निरीक्षण में कलेक्टर ने मतदान केन्द्र के रेम्प सुधारने के लिए कहा।

कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने आने वाले दलों के लिए मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कलेक्टर ने सभी मतदान केन्द्रों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था एवं पंखे व कूलर तथा पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी करने के लिए कहा।

पंचायत सचिव एवं बीएलओ को नोटिस

मतदान केन्द्र क्रमांक 301 प्राथमिक शाला भवन देंदला पर सही तरीके से रेम्प नहीं बनाने पर कलेक्टर ने सचिव बद्रीलाल कराड़ा को कारण बताओ सूचना पत्र देने के निर्देश दिये। इसी तरह मतदान केन्द्र क्रमांक 160 की बीएलओ श्रीमती सलमा शाहीन तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 232 प्राथमिक शाला भवन देंदला बीएलओ अब्दुल करीम खान को द्वारा मतदाता पर्ची वितरण कर मतदाताओं से प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं लेने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

'मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती', तलाकशुदा पत्नी का गला घोट थाने में बोला पति

माही की गूंज, खरगोन।

नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को उसी के घर में गला घोट कर मार दिया। यही नहीं पत्नी की मौत के बाद युवक थाने पहुंचा और पुलिस को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पुलिस ने तुरन्त घटनास्थल पर जाकर देखा और महिला को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला दोनों के बीच विवाद का है।

नगर के काजीपुरा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तलाकशुदा महिला रौशनी की उसके सिरफिरे पति सलीम ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक सलीम ने खुद ही थाने जाकर इसका खुलासा भी किया। उसने थाने में कहा, 'मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती है।' वहीं फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर बेटी की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंची मृतिका की मां अफसाना और पिता शकील ने बताया कि उनकी बेटी रौशनी की शादी सलीम खान निवासी मलकापुर से करीब 5 वर्ष पहले हुई थी।

शादी के करीब एक साल बाद ही बेटी पति की शराब की लत में रोजाना मारपीट से तंग आकर अलग रहने लगी थी, और घरेलू काम-काज के साथ ही शादी ब्याह में काम कर अपना गुजारा कर रही थी। हालांकि, चार साल पहले उनका तलाक भी हो गया था। वहीं उसका पति अक्सर उसके घर जाकर उसे परेशान करता रहता था। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है।

मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती'

वहीं मृतका की मां अफसाना बी ने बताया कि, दोनों के बीच करीब 4 साल पहले तलाक हुआ था। यह घटना सुबह करीब 3 बजे की है। इसके पहले भी 26 जनवरी को वह उनकी लड़की को चाकू मार कर भाग गया था। वहीं उन्होंने बताया कि वह तलाक के बाद भी उनकी लड़की को परेशान करता था और कहता था, 'मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती।'

पति-पत्नी में था विवाद

इधर कोतवाली थाना के एएसआई अजय दुबे ने बताया कि, करीब 4 बजे एक व्यक्ति थाने आया,और उसने सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी रोशनी की गला घोटकर हत्या कर दी है। जिस पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर एक पार्टी सूचना की तस्दीक करने के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हुई और उसकी सूचना सही पाई गई। जिसके बाद मृतका रौशनी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों में विवाद था जिसके चलते यह हत्या हुई है।

एमपी में पीएम मोदी ने की जनसभा, पाकिस्तान का किया जिक्र

माही की गूंज, खरगोन।

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां शुरु हो गईं हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रैली में आई जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि, आपके एक वोट ने 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया है। मैं आज आपके विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं।

खरगोन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे गजेंद्र सिंह पटेल के लिए प्रचार करने पहुंचे पीएम ने कांगेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो माता नर्मदा के तट पर रहते हैं, वे मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं। सदियों से ये क्रम चल रहा है कि नर्मदा तट पर रहने वाला कभी भी मांगने वाले को निराश नहीं करता है।

आपके वोट से बना राम मंदिर- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि, आपके एक वोट ने 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया लेकिन यह तो ट्रेलर है। अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इंडि वालों पर एक कहावत फिट बैठती है, ÷अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।'' पीएम मोदी ने कहा कि, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आरक्षण पर पड़ी है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस आरक्षण को बांटना चाहती है। इन्होंने कर्नाटक में एक रातोंरात फतवा निकाला और जितने भी मुसलमान हैं, उन्हें ओबीसी घोषित कर दिया। इन्होंने पहले से जो ओबीसी है, उनका आरक्षण कम कर दिया। अपने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं।

पीएम ने जनता से पूछा ये सवाल

पीएम मोदी ने रैली में आई जनता से सवाल किया,वे कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करें। क्या भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य...? पिछले दिनों राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान का जिक्र कहा कि उनके विचारों, योजनाओं और कार्रवाईयों का अनुमान मेरे एक्सरे में स्पष्ट होता है। वे आपके बैंक खाते, गहनों, और बहु की शादी में लाने वाले सामान का भी ध्यान रखेंगे। पत्नी की शादी में भी उन्हें अपने एक्सरे से चिन्हित करेंगे। पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस?तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेसी भी घोषणा कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो।

जिन्हें आशा आश्रय ने दिया आशियाना वे अब पक्षियों को दे रहे हैं आसरा

माही की गूंज, बड़वानी।

हर किसी की चाह होती है कि वह अपने परिवार में रहकर ही अपने दैनिक क्रियाकलाप आजीविका आदि का संचालन करे, किंतु ऐसा अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। पारिवारिक कारणों, स्वास्थ्यगत समस्या तथा अन्य अवसादग्रस्त परिस्थितियों के कारण जब कोई व्यक्ति मनोरोग की गिरफ्त में आता है तो वह अपनी चैतन्य अवस्था को खोकर अपने मूल निवास से भी कई बार विरक्त हो जाता है।

कलेक्टर एवं आशाग्राम ट्रस्ट के अध्यक्ष की प्रेरणा से आशाग्राम ट्रस्ट के ट्रस्टी चौकसी वाला ज्वेलर्स के सहयोग से संचालित निराश्रित मानसिक रोगियों के आशा आश्रय गृह में सहज ही देखा जा सकता हैं। यहां रहने वाले सभी मनोरोगियों को आशा आश्रय की टीम के द्वारा विक्षिप्त अवस्था में विभिन्न स्थानों से लाकर आशा आश्रय में चिकित्सा सहित समग्र पुनर्वास से जोड़ा है। यहां रहने वाला मनोउपचारित कोई 13 वर्ष से परिवार से लापता है तो कोई 5 वर्ष से अपने मूल परिवार से दूर है। आशा आश्रय से उपचार पाकर जब यहां के मनोरोगी ठीक होते हैं तभी उनसे उनके मूल परिवार की जानकारी मिलती है और वह विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण कर पुनः अपने परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। दो वर्ष की अल्पावधि में 31 मनोरोगी अपने परिवार में पुनः पहुंचाए जा चुके हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आशा आश्रय में बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब उपचारित मनोरोगीयों ने पक्षियों के लिए आशियाना बनाते हुए नजर आए। आशा आश्रय वासियों ने समाधान पाटील एवं श्रीमती साधना भावसार के मार्गदर्शन में पक्षियों के लिए सुंदर घर बनाकर उन्हें आश्रय गृह के परिसर में वृक्षों पर लगाया गया तथा दाना पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। अपने स्वयं के परिवार एवं घर का महत्व जान चुके इन मनोरोगियों के द्वारा पक्षियों के लिए आसरा बनाना उनके मन से निकले भाव को प्रकट करता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आशा आश्रय परिसर के वृक्षों पर धूप से बचाव के लिए छोटे-छोटे घरों की आकृति के घोंसले बनाए गए जो सभी के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो रहे हैं।

नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा श्रीमती दीपिका मालवीय ने अपने फैसले मे नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी नहारसिंह उर्फ नाहरिया पिता झंझाड़ निवासी मोरतलाई को धारा 5एम/6, पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष एवं 10 हजार रूपए एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे विशेषलोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि, फरियादी ने 6 जनवरी 2022 को पुलिस थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाई थी कि वह दोनो पति पत्नी (बालिका के माता पिता) सुबह मजदुरी करने चले गये थे तथा दोपहर में वापस आये तो बालिका नहीं दिखी। तो उसकी माता ने आसपास गॉव में उसकी तलाश की और मोहल्ले के बच्चो से पूछा तो उन्होने बताया कि वह नाले तरफ टायलेट के लिये गई है। जब वह बहुत देर होने के बाद भी वह नहीं लौटी तो उसके पिता उसको ढूंढते हुये नाले तरफ गये जहां पीड़िता नहीं मिली तो नाले के आस-पास पीड़िता की तलाश करते हुये गन्ने के खेत से उसे आरोपी नहारसिंग अपने कपड़े झकटते हुये जाता हुआ दिखाई दिया। जब पीड़िता के पिता ने नहारसिंग से पूछा की उसकी बालिका को देखा है तो नहारसिंह ने बोला कि मुझे नहीं पता और वहॉ से भाग गया। जब पीड़िता का पिता गन्ने के खेत तरफ बालिका को देखने के लिए गया तो उसकी बालिका जमीन पर बेहोश पड़ी हुयी थी तब बालिका का पिता उसको गोद में उठाकर घर लाया तब बालिका को थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि, आरोपी उसे पोहे खिलाने के बहाने गन्ने के खेत मे लेकर गया और उसके साथ गंदा काम (दुष्कर्म) किया इस कारण वह बेहोश हो गयी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सों एक्ट एवं भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

माही की गूंज, खरगोन। 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रीलिटिगेशन व राजीनामा योग्य न्यायालयीन लंबित प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायालय बड़वाह, सनावद, भीकनगांव, खरगोन, कसरावद एवं महेश्वर में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, अपीले आदि के मामले रखे गये है एवं बैंक, जलकर, विद्युत आदि के प्रीलिटिगेशन मामले रखे गये है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक, नगर पालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर जिला न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट स्तरीय खण्डपीठ का गठन कर जिले में कुल 18 खण्डपीठें गठित की गई है। नियमित न्यायालयीन लंबित प्रकरणों के लिए पृथक से न्यायालय वार 26 खण्डपीठें गठित की गई है।

नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 के संबंध में जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुजीत कुमार सिंह की ओर से समस्त अधिवक्तागण, अधिकारियों, पक्षकारों एवं आम जन को आह्वान किया गया है कि आगामी नेशनल लोक अदालत में भी अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। सभी पक्षकार लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न छूटों का लाभ उठा कर संबंधित प्रकरण के क्षेत्राधिकार अनुसार जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायालयों में अधिकतम प्रकरणों का निराकरण कराकर सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

चलो बूथ की ओर अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

माही की गूंज, बड़वानी। चलो बूथ की ओर अभियान के अंतर्गत बुधवार को कृषि उपज मण्डी प्रांगण सेंधवा में प्रातः 9 बजे से महिला एवं बाल विकास विभाग, बीएलओ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की उपस्थिति में विधानसभा सेंधवा के स्वीप के नोडल अधिकारी मनोज पाटिल द्वारा मतदाता जागरूकता के तहत 13 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई। इस दौरान महिलाओं ने मतदाता जागरूकता के तहत रंगोली बनाकर शहरवासियों को मतदान हेतु प्रेरित किया। उपस्थित सभी ने शहर में रैली निकालकर 13 मई को मतदान करने का संदेश दिया।

20 मई तक किसान कर सकते हैं समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय

माही की गूंज, खरगोन।

रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये जिले में 50 उपार्जन केन्द्र बनाए गए है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2 हजार 275 रुपये और बोनस की राशि 125 रुपये मिलाकर कुल 2 हजार 400 रूपये प्रति क्विंटल के मान से किसानों को भुगतान किया जाएगा। मप्र शासन द्वारा पहले उपार्जन की अवधि 7 मई 2024 तक निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 20 मई 2024 कर दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने समस्त किसान बन्धुओं से अपील की है कि यदि वे समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करना चाहते है तो नजदीकी उपार्जन केन्द्र पर जाकर स्लॉट बुक कर 20 मई 2024 के पूर्व गेहूं विक्रय कर सकते है।

दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाताओं से घर जाकर कराया गया मतदान

माही की गूंज, खरगोन।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक की आयु के ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र जाने में सक्षम नहीं है उन्हें घर पर ही डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खरगोन जिले में ऐसे चिन्हित 711 मतदाताओं से मतदान कराने के लिए मतदान दल 8 मई को उनके घर पहुंचे और मतदान कराया।

दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाताओं से घर पर ही मतदान कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में खरगोन जिले में 51 मतदान दल बनाए गए हैं। जो मतदाता किसी कारण से 8 मई को घर पर नहीं मिल पाए हैं, उनसे मतदान कराने के लिए 9 मई को मतदान दल पुनः उनके घर पहुंचेगा।

मतदान के दिन मतदान केन्द्रों की पल-पल की गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर

माही की गूंज, खरगोन।

आगामी 13 मई को खरगोन एवं खण्डवा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए मतदान के दिन खरगोन जिले के एक हजार 548 मतदान केन्द्रों की पल-पल की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने 8 मई को कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों को समझाया कि उन्हें मतदान के दिन क्या-क्या कार्य करने हैं।

मतदान के दिन मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिले के एक हजार 157 मतदान केन्द्रों पर कैमरे लगाएं जा रहे हैं। वेबकास्टिंग के द्वारा ऑनलाइन कंट्रोल रूम में मतदान केन्द्र की गतिविधियों को देखा जाएगा।

कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग टीम, ईव्हीएम परिवहन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखने वाली जीपीएस टीम और हर दो-दो घण्टे में मतदान प्रतिशत प्राप्त करने वाली टीम तैनात की गई है। सभी टीमों में विधानसभा क्षेत्रवार अलग-अलग कर्मचारी लगाएं गए हैं। कलेक्टर शर्मा ने इस दौरान कहा कि, मतदान केन्द्रों में कैमरे ऐसी जगह लगाएं जाएं जिससे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार, निर्गम द्वार एवं मतदान दल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कैमरे इस तरह से लगाना है कि उसमें वोटिंग कपार्टमेंट (मतदान प्रकोष्ठ) नजर न आए। उन्होंने सभी टीमों के कर्मचारियों से कहा कि वे 12 मई को मतदान दल के मतदान केन्द्र पहुंचने के साथ ही अपना कार्य प्रारंभ कर दें। वेबकास्टिंग टीम मतदान केन्द्र में नियम विरूद्ध गतिविधि पायी जाने पर तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को सूचित करें।

कलेक्टर ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की तर्ज पर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी कंट्रोल रूम तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंट्रोल रूम से मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी संग्रहित करने और मतदाताओं को पर्ची वितरण नहीं करने वाले व इसमें लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने पर्ची वितरण कार्य की रेंडमली जांच करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि, जिले में मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। 13 मई को बूथ अवेयरनेस ग्रुप बीएजी के सदस्य सुबह से ही गांव के मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिन मतदान केन्द्रों पर कम मतदान हो रहा है कंट्रोल रूम से वहां के बीएजी सदस्यों से सम्पर्क करना है।

भाजपा के गढ़ को भेदने की चुनौती, क्या आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस ?

माही की गूंज, धार।

लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं के पाला बदलने से परेशान कांग्रेस के सामने धार निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का गढ़ भेदने की चुनौती है। जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित धार सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को होने वाले मतदान के लिए करीब 19.50 लाख पात्र मतदाता हैं। भाजपा ने धार में अपने निवर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राधेश्याम मुवेल पर भरोसा जताया है।

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार के समर्थक मुवेल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि वह भाजपा से धार सीट छीन लेंगे। मुवेल ने न्यूज़ एजेंसी से कहा, धार के मतदाता सवाल कर रहे हैं कि 2014 से 2019 के बीच सावित्री ठाकुर जब सांसद थीं, तब उन्होंने क्षेत्र के लिए आखिर क्या किया? बेरोजगारी के कारण धार जिले से पलायन के लिए आदिवासी अब भी मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि, सावित्री ठाकुर के पास उनकी निजी उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है और वह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हैं। मुवेल ने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 'मोदी लहर' नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि, मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी बुनियादी समस्याओं से निपटने में नाकाम रही है। धार में लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी मार्च में भाजपा में शामिल हो गए। मुवेल ने कहा कि

अवसरवादी नेताओं के पाला बदलने से हमें लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वे ही नेता भाजपा में जा रहे हैं जो भ्रष्ट हैं।

भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने तीन लाख से ज्यादा मतों से अपनी चुनावी विजय का दावा किया और कहा कि, वह अपने सामने मुवेल की उम्मीदवारी को कोई चुनौती नहीं मानतीं। उन्होंने कहा कि धार लोकसभा क्षेत्र में करीब 10 लाख महिला मतदाता हैं और भाजपा ने महिलाओं के हित में काफी काम किए हैं। सावित्री ठाकुर 'मोदी की गारंटी' के नाम पर धार के मतदाताओं से समर्थन मांग रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 70 साल तक देश की सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी।

भाजपा प्रत्याशी ने कहा, कांग्रेस के राज में आदिवासी क्षेत्रों में भारी भ्रष्टाचार के कारण कुएं, सड़क और तालाब महज कागजों पर बनते थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में इन इलाकों में धरातल पर ठोस काम किए गए हैं। धार लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की आठ सीटें हैं। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से पांच सीट जीती थीं, जबकि भाजपा के खाते में तीन सीट आई थीं।

राजनीतिक विश्लेषक बताते है कि, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान धार में अच्छे प्रदर्शन के बूते कांग्रेस मौजूदा लोकसभा चुनाव में बड़ी खुशफहमी नहीं पाल सकती क्योंकि दोनों चुनावों का गणित एकदम अलग होता है। वहीं, धार के मतदाताओं से बातचीत पर पता चलता है कि उनके लिए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय विषयों के साथ ही भोजशाला विवाद, रेल परियोजनाएं और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं।

यह संविधान बचाने का चुनाव, 150 पर सिमटेगी भाजपा- राहुल गांधी

माही की गूंज, जोबट।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि भाजपा इसे खत्म करना चाहती हैं। भाजपा 400 की पार की बात करती है लेकिन वे 150 पार भी नहीं पहुंचेंगे। अभी आरक्षण में आदिवासी, दलितों और पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए हम आरक्षण को 50 प्रतिशत से आगे बढ़ाने वाले हैं। जिसे जितना आरक्षण चाहिए, उन्हें दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आपके लोग हों, इसके लिए हम जातिगत जनगणना करने जा रहे हैं।

राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के चुनावी प्रवास के दौरान रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में अलीराजपुर जिले के जोबट में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों-करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। अरबपतियों को पैसा दिया, इसलिए अब हमने करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का मन बना लिया है।

महालक्ष्मी योजना में एक गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। उसमें से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में एक हर साल एक लाख रुपये डालेंगे। 8 हजार 500 रुपये हार माह उस दिन तक डाले जाएंगे, जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता।

उन्होंने कहा कि, हम आपके लिए एमएसपी पर कानून लाएंगे। जैसे ही सरकार आएगी हम सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। दलित-पिछड़ा वर्ग और गरीबों के लिए हम योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसके लिए हम ये योजना लेने जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट को एक साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। इससे हर युवा के बैंक अकाउंट में हम प्रति वर्ष एक लाख रुपए डालेंगे।

शादी की खुशियां मातम में बदली

माही की गूंज, उज्जैन।

मंगलवार-बुधवार रात में नागदा-उन्हेल रोड पर एक ऐसी भयावह दुर्घटना घटित हुई, जिसमें रतलाम से खरीददारी कर वापस से आ रहा एक परिवार एक डम्फर में पीछे से टकरा गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय उज्जैन पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल लाते समय दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर घायलों में से तीन को इंदौर रेफर किया गया है।

उज्जैन तहसील में रहने वाले वाघेला परिवार की बेटी अंजलि (19) की कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी। जिसके बाद शादी से संबंधित खरीदारी करने के लिए पूरा परिवार रतलाम गया था, जहां से वह कार से उज्जैन लौट रहे थे कि तभी उज्जैन-उन्हेल रोड पर हरियाली ढाबे के पास एक मोटरसाइकिल और डम्फर के बीच भिड़ंत हो गई।

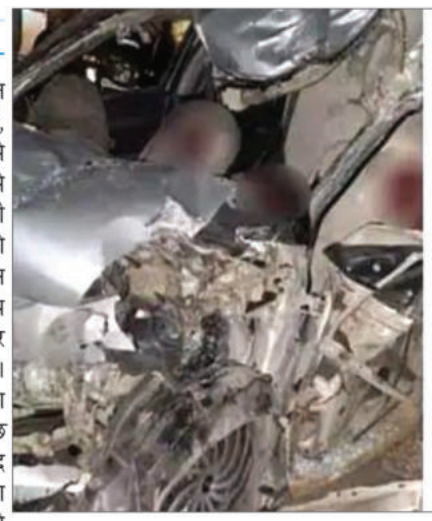

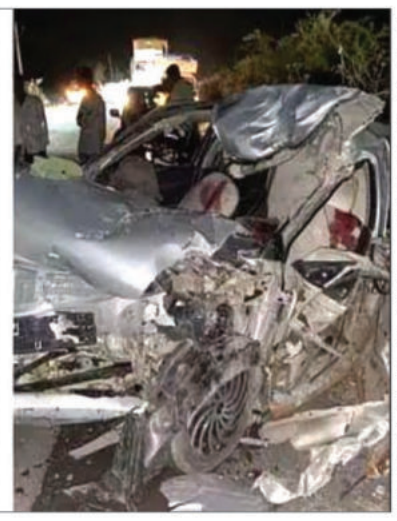

डम्फर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक रामेश्वर उम्र 40 वर्ष निवासी कुंडला तो घायल हुआ ही, लेकिन डंपर मोटरसाइकिल की भिड़ंत के कारण कार चालक सादिक उम्र 18 वर्ष निवासी मंडवासा कार पर संतुलन नहीं रख पाया और यह यह कार डम्फर से जा टकराई, जिससे कार में बैठे रामेश्वर वाघेला के साथ ही सुशीला पति भगवान सिंह, अंशिका उम्र 14 साल, संदीप उम्र 20 वर्ष, अंजलि उम्र 19 वर्ष, चंदा उम्र 30 वर्ष, पूजा उम्र 12 वर्ष, निहारिका उम्र 5 वर्ष और सावित्रीबाई उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इन घायलों को राहगीरों की सहायता से पुलिस ने तुरंत उज्जैन जिला चिकित्सालय पहुंच है, लेकिन उज्जैन लाते समय सावित्रीबाई उम्र 40 वर्ष और पूजा उम्र 12 वर्ष की मौत हो गई। जबकि सुशीला बाई, अंशिका और संदीप की हालत अत्यंत गंभीर थी, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। मामले की जानकारी लगते ही उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे जहां उन्होंने घायलों के हालचाल जाने और सभी को अच्छे से उपचार दिए जाने की बात कही।

गिरते जल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों को उपलब्ध करवाए पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने बताया कि, पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी होने के कारण कई जगह से जल प्रदाय न होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस संदर्भ में कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल निगम अलीराजपुर के द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा चौहान, ईई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एसआर मेड़ा एवं जीएम जल निगम कुलदीप सिंह अलीराजपुर उपस्थित थें। इस दौरान ईई मेडा ने कलेक्टर डॉ. बेडेकर को अवगत कराया कि जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही समस्त 156 योजना की समीक्षा की। इसमें से 65 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है 61 प्रगतिशील एवं शेष 30 पर टेस्टिंग का कार्य चल रहा है।कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने बताया कि, जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण होने एवं गर्मी के कारण गिरते जल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों को पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई भी परिवार को पेयजल के पानी के लिए परेशान न होना पडे। उन्होने इस बैठक के दौरान ही हरसवाट के ग्राम के ग्रामीणों से फोन पर चर्चा कर पेयजल के स्रोतों की जानकारी ली। कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने जल निगम के कार्यो की समीक्षा भी की। उन्होने बताया कि आगामी दिनों में वह स्वयं ककराना में निर्माण हीन इनटेक वैल का निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बैठक से अनुपस्थित होने पर पांच उप यंत्री को कारण बताओं सूचना पत्र देने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यंत्री उपस्थित थे।

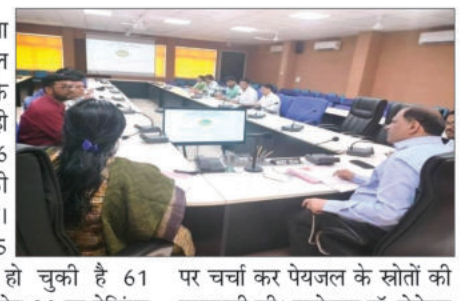

36 गंभीर अपराधों की कि विस्तृत समीक्षा

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जघन्य सनसनीखेज 36 गंभीर अपराधों की विस्तृत समीक्षा की गई। अलीराजपुर जिले के जघन्य एवं सनसनीखेज के जो प्रकरण चिन्हित किए गए है, उसके सम्पूर्ण विवरण की फाईल बैठक में प्रस्तुत की गई। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने जघन्य एवं सनसनीखेज गंभीर अपराधों की श्रेणी वाले प्रकरणों के आरोपियों एवं अपराधियों को किसी भी तरह की राहत न दिए जाने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिला लोक अभियोजन संचालक राजीव गरवाल, समेत संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

भोजशाला के गर्भगृह में 18 खंडों में खुदाई कर हटाई मिट्टी

माही की गूंज, धार।

न्यायालय के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ज्ञानवापी की तर्ज पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) का सर्वे कार्य बुधवार को 48वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार दोपहर के बाद सर्वे टीम ने गर्भगृह में चिह्नित 18 स्थानों के खंडों में खोदाई के साथ मिट्टी हटाने का काम किया। इस स्थान पर चार दीवारों की संरचना मिली थी। 20 सदस्यों की टीम ने भोजशाला में सर्वे किया। अब मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई है। इससे खोदाई कार्य में तेजी आई है। वहीं कमाल मौलाना दरगाह के पास की दीवार से मिट्टी हटाने का काम भी किया गया।

भोजशाला के गर्भगृह में वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी भी गई है। टीम द्वारा भोजशाला के भीतरी परिसर में रखें स्तंभ व शिलालेख की विशेष फोटोग्राफी की गई है। वहीं यज्ञ कुंड के पास भी खोदाई का काम हुआ है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि, भोजशाला में मंगलवार को खोदाई के अलावा क्लीनिंग, ब्रशिंग के साथ वीडियोग्राफी का काम हुआ है। दक्षिण, पश्चिम में मिट्टी हटाने का काम किया गया।

आसिफ पिता अनवर खान को किया जिला बदर

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेडेकर द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क और गंभीर है। इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ जिला बदर सहित अन्य सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आसिफ पिता अनवर खान (30) निवासी चंद्रशेखर आजाद नगर द्वारा लगातार अपराध घटित किया जाने पर 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। इन्हे अलीराजपुर राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बड़वानी की राजस्व सीमा से बाहर रहने के लिए आदेशित किया गया है।

सूरत से उज्जैन आई तीन युवतियां शिप्रा में डूबी, होमगार्ड के जवानों ने बचाई जान

माही की गूंज, उज्जैन।

गुजरात के सूरत से उज्जैन दर्शन करने के लिए आई तीन युवतियां मंगलवार सुबह रामघाट पर पहुंची थी। जहां तीनों शिप्रा नदी में स्नान कर रही थी। उसी दौरान तीनों युवतियां गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। मौके पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

होमगार्ड सैनिकों ने बताया कि, मंगलवार को पूजा, जिया, सरिता तीनों निवासी सूरत गुजरात अपने परिवार के सदस्यों के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन आई थी। यहां रामघाट पर शिप्रा नदी में स्नान कर रही थी। तीनों नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गई। जिस दौरान युवतियां डूब रही थी, उस समय युवतियों की मां मोबाइल से उनका वीडियो बना रही थी। बेटियों को डूबते देख उसने शोर मचाया तो होमगार्ड सैनिकों ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर तीनों युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि पंचकोसी यात्रा की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त होमगार्ड सैनिकों व शिप्रा तैराक दल के सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है।

महामंडलेश्वर मंदाकिनी पर लगा साधु-संतों से लाखों की ठगी का आरोप

माही की गूंज, उज्जैन।

महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में उज्जैन पुलिस ने महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी सहित दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जैसे ही मंदाकिनी पुरी पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उनका इलाज उज्जैन के अस्पताल में चल रहा है।

निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश्वरानंद गिरी महाराज ने उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाने में मंदाकिनी पुरी और उनके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महंत का कहना है कि, उन्हें महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर मंदाकिनी पुरी ने उनसे साढ़े 7 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद जब महामंडलेश्वर बनाने की बारी आई तो वह बहानेबाजी करने लगीं।

धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर

इसके बाद सुरेश्वरानंद गिरी महाराज ने थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस मंदाकिनी पुरी को गिरफ्तार कर पाती, इसके पहले उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। अब इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने मंदाकिनी पूरी को अखाड़े से बाहर कर दिया है।

मुझे झूठे मामले में फंसाया- मंदाकिनी

महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने एफआईआर दर्ज होने के मामले में कहा है कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि, उनके शिष्य ने उन्हें फंसा दिया है। दोनों के बीच का कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंदाकिनी पुरी और सुरेश्वरानंद के बीच पैसों को लेकर भी बातचीत हो रही है।

इसमें मंदाकिनी पुरी यह भी कह रही हैं कि यदि उनका काम नहीं होता तो वह अपनी राशि वापस ले जा सकते हैं। उनके पास यह रकम अमानत के तौर पर पड़ी है।

कई साधु संत सामने आए

कथा वाचक भगवान बापू ने भी मंदाकिनी पुरी पर लाखों रुपए लेकर महामंडलेश्वर बनाने का आरोप लगाया है। इसी तरह पंडित सुमन महाराज ने भी मंदाकिनी पर बीजेपी नेताओं के नाम पर पैसे ले कर उन्हें राज्यपाल तक बनाने की बात कही थी।

राजू के असल हत्यारे आखिर कौन...? पुलिस पूरे मामले का करेगी खुलासा या फिर अधर में रखेगा मामला...

तलवार से वार करने वाला व्यक्ति ही निकला मृत तो किस आधार पर फरियादी ने मृत व्यक्ति को भी चश्मदीद बताया हत्यारा... ?

माही की गूंज, खवासा।

हमारी न्याय व्यवस्था भी यही कहती है कि, भले ही गुनहगार को सजा नहीं मिले तो एक बार चलेगा लेकिन कोई बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। 30 अप्रैल मंगलवार रात्रि में रतनाली सरपंच बबली बाई के पति राजू भूरिया की हुई हत्या में भले ही फरियादी बन चश्मदीद व नामजद आरोपीतो को हत्या करना बताया गया है। परंतु आज भी यह हत्या का कारण संदेह के घेरे में ही होकर चर्चा का विषय बना हुआ है।

उक्त हत्या के बाद 3 मई को कल्याणपुर थाने के अंतर्गत ग्राम भगोर में नेगडी नदी के पास एक अज्ञात महिला का शव पत्थरों से कुचला हुआ मिला था। उक्त महिला की पहचान सतुराबाई पति अपसिंह सिंगाड़िया निवासी बरोड़ के रूप में हुई थी। पुलिस अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में जुटी और सतूरा बाई का घटना के पूर्व किसके साथ गई थी का सुराग पकड़ा और तीन दिन में ही पुलिस ने महिला के कथित प्रेमी ने लेनदेन के मामले में अक्सर विवाद होने के चलते महिला की हत्या करने का खुलासा किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजू की हत्या के मामले में कई तरह के संदेहास्पद बात वारदात के पूर्व से लेकर वारदात एवं वारदात के बाद फरियादी द्वारा चश्मदीद चार आरोपितों के नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी उक्त हत्या की सनसनी वारदात आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

लेकिन पुलिस, वारदात का असल खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में क्षेत्र में संशय बना हुआ है कि, क्या पुलिस पूरे मामले का करेगी खुलासा या फिर अधर में ही रख देगी उक्त वारदात को...?

क्षेत्र वासियों का संशय होना भी सही है क्योंकि कोई भी इस तरह की दुखदायी वारदात जोर, जारु और जमीन के चक्कर में ही होती है लेकिन उक्त वारदात व वारदात के बाद बताया जा रहा कारण महज ही भांजगड़ी प्रथा है। जिले में चलने वाली भांजगड़ी प्रथा का राजू महज एक अगुआ (आगेवान) था न की किसी तरह का व्यक्तिगत विवाद! वहीं राजू की हत्या के पूर्व दिन में चली भांजगडी का मामला यह था कि, रतनाली ग्राम की ही दो लड़कियों की अगवा हो जाने की रिपोर्ट लड़कियों के परिवार ने पुलिस को की थी। दोनों मामलों में पुलिस ने 363 में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी कि, 30 मई को लड़कियों के परिजन व ग्रामवासी ही जिसमें सरपंच पति राजू भी शामिल था जिसमें दोनों लड़कियों को विपक्षी परिजनों के साथ लेकर चौकी पर आए थे। खवासा की पुलिस, लडकी परिवार के साथ दोनों लड़कियों के बयान करवाने हेतु थांदला ले गई। जहां धारा 161 में अकेले में महिला पुलिस अधिकारी ने बयान लिए। वही 164 में दोनों लड़कियों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए दोनों लड़कियों ने बयान में स्वैच्छिक रूप से जाना बताया। जिसके उपरांत विपक्षी के विरोध कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। खवासा पुलिस बयान के बाद उनके परिजनों के साथ पुलिस की गाड़ी में ही आए और परिजनों के सुपुर्द लड़कियों को कर दिया।

चारो पक्षों के परिवार व ग्रामवासी के साथ राजू भी भांजगडी निपटाने में था। चल रही भांजगड़ी के दौरान ही चौकी परिसर में ही बैठी दोनों संबंधित लड़कियां सामने पक्ष वालों के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। जिसे देख लड़की पक्ष के साथ खासकर राजू जो कि ग्राम का सरपंच पति होने के नाते पुलिस पर दबाव बनाया व आरोप लगाया की पुलिस ने लड़कियों को सामने वाले परिवार के सुपुर्द कर दिया। उक्त बात को लेकर राजू की भी खवासा पुलिस से झड़प हुई।

तथा पुलिस भी हरकत में आई और चौकी परिसर से गई लड़कियों की तलाश में पकड़ने हेतु चली गई और कुछ समय बाद दोनों लड़कियों को पुलिस ले भी आई और फिर से दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। लेकिन चारों पक्षों में मामले में कोई सुलह नहीं होकर अधर में रहा और सब चौकी से बिखर गए। वहीं राजू ने अपने भाई एवं परिचितों के साथ शराब के साथ भोजन भी बजाना मार्ग स्थित एक ढाबे पर किया।

राजु भुरिया की हत्या का पुलिस करे पुरा खुलासा।

बात यह सामने आई थी कि, थांदला मार्ग स्थित शराब के ठेके से शाम करीब 6 बजे एक शराब का अद्दा राजू ने लिया जिसमें कुछ पैसे भी बाकी किये। वहीं रात 8 बजे करीब एक अन्य व्यक्ति को शराब लेने पुनः उस ठेके पर भेजा और वह भी पैसे बाकी किये। जिसमें फोन पर सेल्समैन या अन्य को थांदला मार्ग पर स्थित स्कूल के आसपास ही एक किसान के खेत में बैठकर शराब पीना बताया लेकिन अब बात सामने आई तो पता चला कि बाजना मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर करीब 2 बजे अपने दो-तीन साथियों के साथ राजू शराब पीने गया था। थोड़ी देर बाद पुनः राजू चौकी पर आ गया जिसके बाद करीब 5 बजे 1 किलो मांस बनाने हेतु ढाबा संचालक को दे गया फिर करीब 7 बजे राजू ढाबे पर पहुंचा और कुछ परिचित व भाई परिवार के व्यक्ति भी ढाबे पर पहुंच गए। राजू ने सहजता के साथ सभी का आत्मीय स्वागत के साथ सभी को बिठाया और उनको भी शराब पिलवाई एवं खाने में 1 किलो मांस में ही खुश खुश होकर में अकेला नहीं खाऊंगा सब मिलकर खाएंगे कहकर सभी को खाना खिलाया और सभी ने शराब का सेवन भी लिमिट में ही किया था बताया जा रहा है।

करीब साढ़े 8 बजे बाद सभी अलग-अलग अपनी गाड़ियों से बस स्टैंड की ओर निकले। बस स्टैंड पर भी गांव के लोगों को ज्युस पिलाया, जिसके बाद बच्चों के लिए एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम व कुल्फी लेकर घर जा रहा था की घात लगाए जान या अनजान..? हत्यारो ने थांदला मार्ग पर स्थित एक निजी स्कूल के पास सड़क पर ही धारदार हथियार से गाव व समाज के प्रति अपनी सहानुभूति रखने वाले राजु भूरिया की बेरहमी से हत्या कर दी।

उक्त हत्या के बाद वारदात का जो स्वरूप बताया जा रहा है, वह पूर्णतः संशय की स्थिति में हीं है।

बताया गया मुख्य आरोपी चार वर्ष पूर्व ही मर चुका

फरियादियों द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में राजू की हत्या करने में मुख्य आरोपी जीवणा गामड़ को बताया जा रहा है वही उसे मरे हुए चार-पांच वर्ष हो गए बताया जा रहा है। जबकि रिपोर्ट में बताया गया की मोटरसाइकिल की लाइट में देखा कि, जीवणा गामड़ ने अपने हाथ में तलवार लिए हुए था, जिसने राजू के सिर पर तलवार से जानलेवा वार किया जिससे राजू जमीन पर गिर गया, जिसके बाद जीवणा गामड़ के साथी अनिल गामड़, सोमा गामड़ व महेंद्र गामड़ ने पत्थर उठाकर राजू के सिर पर मारे। फरियादीगण बचाने के लिए गये लेकिन जीवडा सहित चारों ने तलवार व पत्थर लिए मारने दौड़े इस पर फरियादियों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागे। जीवणा एवं उसके साथी के जाने के बाद फरियादीगण एवं अन्य व्यक्ति घटनास्थल पहुंचे जहां राजू मृत अवस्था मे पड़ां था। लेकिन दूसरा पहलू यह की तलवार से हमला करने वाला मुख्य व चश्मदित आरोपीत जीवणा को बताया जा रहा है उस जीवणा को मरे कई साल हो चुके हैं ऐसे में मरा हुआ व्यक्ति चश्मदीद हत्यारा कैसे हो सकता है...?

वही यह भी बताया जा रहा है कि बाकी तीन में एक व्यक्ति राजस्थान में मजदूरी करने गया हुआ था और पुलिस की लोकेशन में भी शायद यही सामने आ रहा है कि एक आरोपित बाहर मजदूरी के लिए ही गया हुआ था। पुलिस ने चश्मदित बताए गये तीन आरोपितों को मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं जीवणा के मृत होने के दस्तावेजों की जांच करने की बात पुलिस कर रही है। वहीं जीवणा की मृत होने के बात सामने आने पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि, किसी पुराने विवाद में फरियादियों ने राजू की हत्या करने में मृत जीवणा सहित चार आरोपीतो के नाम लिखा दिए है या फिर और कोई रहस्य हो ? जो घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस सामने नहीं ला पाई है । परंतु क्षेत्र में सभी से मिलनसार रखने वाले राजु की हत्या महज एक रहस्य बनकर नहीं रह जाए इसके लिए अब भी क्षेत्र वासी पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि वह उच्च स्तरीय व वैज्ञानिकों की सहायता के साथ हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर राजू की हत्या का संशय को दूर करें। अगर पुलिस मामले को गम्भीरता से नही लेती है और हत्या के मुख्य कारणो का खुलासा नही करती है तो क्षेत्र में ये ही चर्चा रहेगी की कही असल अपराधी जेल से बाहर है और अन्य अपराध की रचना रच रहा है वही कोई बेगुनाह सलाखो के अंदर है।

देश में राजनीतिक दलों की स्थिति मतलब हमाम में सब नंगे

दल-बदल, ब्लेक मेलिंग, खरीद-फरोख्त पर आकर टिक गई राजनीति

खतरे में लोकतंत्र, खुले आम उड़ाई जा रही धज्जियां

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो हिंदुस्तान की राजनीति अब किसी से छुपी या दबी नहीं रही है। राजनीति में हर वह हथकंडा अपनाया जा रहा है जो शायद अपनाया नहीं जाना चाहिए था। मगर यहां अब लोकतंत्र की हत्या को गर्वोक्ति समझा जाने लगा है। इसलिए देश के लोकतंत्र में राजनीति की गलियों में ईमानदारी की कामना करना बेमानी ही होगा। जिस तरह की राजनीति आज के दौर में देखने को मिल रही है वह बहुत ही भयावह दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक दलों ने अपनी सारी की सारी मर्यादाएं छिन्न-भिन्न कर के रख दी है। हर वह काम जायज समझ कर किया जा रहा है जो नाकाबिले बर्दास्त है। भाषाई मर्यादा तो बहुत पहले ही राजनीति से गायब हो चुकी है। अब तो सिर्फ शारीरिक नंगाई ही बाकी दिखाई दे रही है। इसके अलावा तो राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा नंगापन दिखा दिया है। राजनीति के नाम पर कई ऐसे काम किए जा रहे है जो राजनीति की अस्मित्ता को तार-तार कर रहे है।

देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माया और आमजन शर्माया हुआ नजर आ रहा है। हर कोई राजनीति के इस स्तर को झूकी और शर्मिंदगी भरी निगाहों से देख रहा है। मगर आवाज उठाने में हर कोई लाचार नजर आ रहा है। मीडिया सत्ता को धोग दे रही है तो वहीं कुछ कलम के सिपाही मुखर होकर अपनी बात आमजन तक पहुंचा रहे है। मगर इनकी आवाज को भी सत्ता निगल लेना चाहती है। प्रशासन, पार्टी एजेंट की तरह काम पर लगा हुआ है। तो पार्टी कार्यकर्ता अपने आपको पीएम, सीएम से कम नहीं आंक रहे है। सत्ता के ईशारों पर नाचने वाली प्रशासन रूपी नचनिया इस तरह नाच रही है कि घुंघरू टूट जाए। निर्वाचन आयोग भी लग रहे आरोपो के साथ अब शक के घेरे में है और सरकार का एजेंट माना जा रहा है। देश के हालात अब लोकतंत्र और राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे है। केंद्र में बैठी

सरकार अब सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है। विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने पर आमदा है। जो राजनीतिक दल सत्ता के खिलाफ हुंकार भरता है उसके नेता और लीडर बेवजह ही जेलों में ठूंस दिए जाते है। विपक्ष के नेता सत्ताधारियों से अपनी जान छुड़ाने खुद उनके साथ हो जाते है। सरकारी एजेंसियो का दुरूपयोग खुलकर हो रहा है, ये सरकारी एजेंसियां बिना किसी तथ्य और सबूत के बेलगाम घोड़े की तरह सत्ता के ईशारों पर दौड़ रही है के भी आरोप है। राजनीति अब दल-बदल, ब्लेक मेलिंग, खरीद-फरोख्त पर आकर टिक गई है। सत्ताधारी दल ने पूरे लोकतंत्र को चिढ़ाते हुए अपनी उटपटांग हरकतें शुरू कर दी है। विपक्षी दल के नेताओं को येन-केन प्रकारेण शाम, दाम, दंड, भेद अपना कर अपने साथ मिलाया जा रहा है। जैसा कि अब तक प्रचलित हो चुका है कि, सत्ताधारी दल यानी वॉशिंग मशीन। अगर आप सत्ताधारी दल के साथ हो लिए तो समझो आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे। इसके कई उदाहरण पूरे देश में भरे पड़े है, लेकिन सत्ताधारी दल इसे सिरे से नकारता ही नजर आ रहा है मगर यह पब्लिक है सब जानती है...

सूरत और इंदौर कांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। इन दो जगहों पर खुलकर ओछी राजनीति देखने को मिली है। जहां विपक्ष को पूरी तरह से मिटाने की कोशिशें की गई है। बिना चुनाव के सत्ताधारी दल ने ऐसा खेल खेला कि विपक्ष को चारों खाने चित कर इन सीटों पर अपना कब्जा येन-केन प्रकारेण बना ही लिया। देश में चुनाव के पहले ही 543 मे से दो सीटें कब्जा ली गई। हालांकि ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। मगर इससे राजनीति का स्तर मापना आमजन के लिए आसान हो गया है। वैसे भी विपक्ष हमेशा सत्ता पर कई तरह के सवाल दागता आया है। चाहे एवीएम हेकिंग की बात हो या माफियाओं, गुंडों को संरक्षण देने या फिर देश के धन्नाओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग की, देश की सम्पत्ती बैचने और देश को बरबाद करने की। विपक्ष हमेशा से ही इन आरोपों को सत्ता पर लगाता आया है। मगर सत्ताधारी दल की बहुमत वाली सरकार ने किसी को भी अपनी गिनती में नहीं लिया।

देश के राजनीतिक हालात ऐसे बन गए है कि, लोकतंत्र खतरे में आकर खड़ा हो गया है! खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया गया है कि वह अब सिर्फ देश की आमजनता से आस लगाए बैठा है। बाकी उसके हाथ में शायद कुछ है ही नहीं। हालात ऐसे हो गए है कि अब एक क्षत्र राज दिखाई देने लगा है। लोकतंत्र की आवश्यकता गौण दिखाई पड़ रही है। देश की राजनीतिक स्थिति मानों हमाम में सब नंगे की तरह दिखाई पड़ रही है।

गुजरात मॉडल की घोषणा टाय-टाय फिस्स....

अनदेखी: माही नहरों से लीकेज रुक जाए तो बामनिया, खवासा, थांदला और मेघनगर तक पहुंच सकता है पानी

माही की गूंज, बरवेट। जगदीश प्रजापति

माही नदी का पानी क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन इसी पानी की कदर अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। नतीजा जितना पानी सिचाई के लिए उपयोग होता है उससे दो गुना पानी यूं ही व्यर्थ बह जाता है। इसे रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माही नहरो को गुजरात मॉडल की तर्ज पर पक्की बनाने के लिए घोषणा की थी लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नही दिया जा रहा और घोषणा महज टाय-टाय फिस्स ही साबित होकर व्यर्थ ही पानी बह रहा है। इस पानी को अगर व्यर्थ बहने से रोक लिया जाए तो सिचाई के लिए कमांड एरिया बढ़ सकता है। वही बामनिया, खवासा, थांदला, मेघनगर क्षेत्र तक पानी पहुच सकता है।

मामला माही नदी से निकली नहरों का है। दरअसल, माही डेम से निकल रही माही नहर निर्माण के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ है। नहरो के निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई, जिससे सेकड़ो जगह से पानी लीकेज होता है। नहर से लीकेज ओर सीपेज से निकलने वाला पानी छोटे-छोटे नदी, नालों में व्यर्थ बह जाता है। जो अनुपयोगी है। लेकिन इस पानी को रोकने के लिए अभी तक माही परियोजना के अधिकारी, जलसंसाधन विभाग, विधायक, सांसद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पेटलावद नगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान माही नहरो को गुजरात की नहरो की तर्ज पर पक्की बनाने की घोषणा की थी।

अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा माही का पानी

दरअसल इस लीकेज के कारण माही नहर के अंतिम छोर तक रहने वाले किसानों के खेतो तक पानी, नहर के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है। इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है। यहां के किसानों का कहना है कि, हर वर्ष बल्क में व्यर्थ बह रहे पानी के कारण हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है। जिसकी वजह से हमें नुकसानी उठानी पड़ती है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नही दें रहे है। अगर घोषणानुसार गुजरात मॉडल में नहरों को बना दिया जाए तो अंतिम छोर तक पानी पहुच सकता है।

पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकी जाए तो आधा जिला हराभरा हो सकता है

बामनिया के भाजपा नेता अजय जैन ने बताया कि, माही नहरों से लीकेज के कारण व्यर्थ बर्बाद हो रहे पानी को रोकने का प्रयास किए जाने चाहिए। अगर व्यर्थ बह रहे पानी को रोक दिया जाए तो नहरों का विस्तारीकरण कर बामनिया, खवासा, थांदला तक माही का पानी पहुच सकता है। जिससे सिचाई के लिए कमांड एरिया बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में किसानों के साथ क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से जूझना नही पड़ेगा। किसानों को अप्रेल, मई माह में भी पानी भी मिल सकता है। जिससे वे गर्मी के मौसम में भी फसलों का उत्पादन कर सकते है। साथ ही अप्रेल ओर मई माह में भीषण गर्मी पड़ने से क्षेत्र के सभी नदी-नाले सूख जाते हैं। इस पानी को बचाकर नदी-नालों में उस समय छोड़कर फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। ताकि भीषण गर्मी में पानी की समस्या न हो।

0 से 18 किलोमीटर तक ज्यादा सीपेज होता है पानी

पेटलावद निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता भेरूलाल जाजपर ने बताया कि, माही डेम से निकलने वाली नहरो में सबसे ज्यादा लीकेज जीरो से 18 किलोमीटर तक हो रहा है। क्योंकि वहां पर हार्ड रॉक ओर नहरो की गहराई ज्यादा है। ओर इतने किलोमीटर में ज्यादा खेती भी नही है और सिचाई का रकबा भी कम है। अगर नहरो को गुजरात की तरह पक्की बना दिया जाए तो नहरो का दायरा बामनिया ओर थांदला, मेघनगर तक बढ़ सकता है। इसके लिए विभाग को स्टीमेट बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को भेजना चाहिए ओर मध्यप्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से अलग से फंड की डिमांड करनी चाहिए, अब इस क्षेत्र के विधायक, केबिनेट मंत्री भी है तो स्वर्गीय दिलीपसिंह भूरिया के हरित झाबुआ के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422